● वर्ष-3
● अंक-269
रायपुर, गुरुवार
20 जून 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› जब किसी आलसी के साथ काम करना...

विष्णुदेव मंत्रिमंडल बैठक में विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय

विदेशी शराब की थोक खरीदी की लायसेंसी व्यवस्था समाप्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है।

इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के पास होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछडा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राधिकरणों के गठन के पश्चात् अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा-टोला, पारा-मोहल्लों, वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया, जिसके चलते प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया, बल्कि इनके कार्यों में पारदर्शिता मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन एवं निधि नियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल ने विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 ए बी अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाईयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लायसेंस धारकों द्वारा किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को दे दी है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी, 2024 को पारित अशासकीय संकल्प के तहत प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जहाँ अनुसूचित जनजातियों की 25 प्रतिशत से अधिक बहुलता है, उन क्षेत्रों के गांवों एवं ब्लाकों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में शामिल किया गया है। प्राधिकरण अपना कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर, मतैक्य से मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। झ

प्राधिकरण को सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाया जाएगा। वर्तमान में प्राधिकरण के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों के लिए बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की ओर से उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन किया गया।

14 खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों के बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा 'आज कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर कैबिनेट ने एमएसपी को मंजूरी दी है। धान का नया एमएसपी 2,300 रुपये किया गया है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपए अधिक है।' खरीफ की फसलों के नए एमएसपी पर अश्विनी वैष्णव ने बताया 'आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब दो लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले सीजन से 35000 करोड़ रुपये अधिक है।

केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसले ये रहे- कपास का एमएसपी 501 रुपये बढ़ा, कैबिनेट ने 2024-25 खरीफ फसल सीजन के लिए धान के एमएसपी में 117 रुपये से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी, कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है, सरकार की ओर से 2 लाख गोदाम बनाने का काम किया जा रहा है, कैबिनेट ने 2024-25 खरीफ फसल सीजन के लिए धान के एमएसपी में 117 रुपये से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी, महापालगर-बधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी, कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपये की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी।

यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच की घोषणा

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाली स्वायत्त एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को हुई यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया।

300 शहरों में 1200 से अधिक केंद्रों पर कराई गई थी परीक्षा

9 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी परीक्षा

मेडिकल इंट्रेंस परीक्षा रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट परीक्षा को भी रद्द करने का एलान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी-नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। सरकार के मुताबिक परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, एनटीए ने यूजीसी-नेट परीक्षा 18 जून, 2024 को देश के विभिन्न शहरों में दो चरणों में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में आयोजित की थी। 19 जून यानी आज यूजीसी को परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से कुछ इनपुट मिले। इन जानकारियों से प्रथम दृष्टया संकेत मिला कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया होगा।

बयान में कहा गया कि परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाए। एक नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। इसके साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से कई तीखे सवाल किए। अदालत ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मेडिकल की इस परीक्षा के लिए छात्र-छात्राओं की मेहनत पर बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को विरोधात्मक भाव से नहीं देखा जाना चाहिए।

बृजमोहन का मंत्री पद से इस्तीफा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बुधवार को मंत्री पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया। जैसा कि कयास लगाए जा रहा था कि श्री अग्रवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को रायपुर दक्षिण के विधायक के तौर पर विधानसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंपा।

इस दौरान विधायक अजय चंद्राकर, विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, पूर्व सांसद सुनील सोनी सहित कई नेता मौजूद थे। इस्तीफे के बाद श्री अग्रवाल ने कहा, एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं। आप सभी का प्यार और दुलार मिलता रहेगा। मैं रायपुर दक्षिण की जनता से माफी मांगता हूं। मुझे विधायक का पद नई दायित्व के साथ छोड़ना पड़ा है। मैं संसद में जनहित के मुद्दों को उठाता रहूंगा। केंद्र में मंत्री नहीं बन पाने का मुझे मलाल नहीं है।

ली शिक्षा विभाग की बैठक- इस्तीफा देने से पहले बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा मंत्रालय की अहम मीटिंग ली. इस मीटिंग में उन्होंने प्रदेश में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रकिया को लेकर चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर मंथन किया. इस मीटिंग में स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्लास बनाने पर भी बात हुई. 17 जून को विधायक पद से दिया था इस्तीफा- बृजमोहन अग्रवाल ने 17 जून को विधायक पद से रिजाइन किया था. उन्होंने छत्तीसगढ़ विधासभा के स्पीकर रमन सिंह के घर जाकर अपना इस्तीफा सौंपा था. बृजमोहन अग्रवाल रायपुर लोकसभा सीट से सांसद बने हैं इस वजह से उन्होंने विधायक पद से अपना त्याग पत्र सौंपा. अब बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्रीपद से इस्तीफा सौंपा है.

प्रमुख समाचार

नवीन पटनायक ओडिशा विस में बने नेता विपक्ष

नई दिल्ली। 2000 के बाद पहली बार हार का सामना कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विपक्ष के नेता (एलओपी) के रूप में नियुक्त होने के बाद ओडिशा विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पटनायक ने कहा, हमने हाल ही में हुए चुनावों में निर्वाचित बीजद विधायकों की एक बैठक की थी। मैंने उन्हें बधाई दी और धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे विपक्ष के नेता और बीजू विधायक दल के नेता के रूप में चुना है। ओडिशा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कहा, मैं और मेरी पार्टी स्वाभाविक रूप से ओडिशा के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि हमने हाल ही में बीजद विधायकों की एक बैठक की, जो हाल के चुनावों में चुने गए हैं। मैंने उन्हें बधाई दी और धन्यवाद दिया। पटनायक ने आगे कहा कि उन्होंने मुझे विपक्ष के नेता और बीजू विधायक दल के नेता के रूप में चुना है। मैंने विधानमंडल में बीजद के उप नेता के रूप में प्रसन्ना आचार्य, मुख्य सचेतक के रूप में प्रमिला मल्लिक और बीजद के उप मुख्य सचेतक के रूप में प्रताप केशरी देब के नए पद की भी घोषणा की है।

केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मिल गए पुख्ता सबूत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। केजरीवाल उत्पाद नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। बुधवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जानना चाहा कि न्यायिक हिरासत बढ़ाने की जरूरत क्यों है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी के वकील ने कहा कि विनोद चौहान को गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से के कविता के निजी सहायक से रु. 25 करोड़ मिले थे। सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि रु. 25 करोड़ रु. 100 करोड़ के मनी ट्रेल का हिस्सा था। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक रु. 45 करोड़ का पता लगाया जा चुका है।

रूपौली उपचुनाव में बीमा भारती जद(यू) से चुनाव लड़ेंगी

पूर्णिया। बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती ने रूपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भारती रूपौली सीट का कई बार जनता दल (यूनाइटेड) की विधायक के तौर पर प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए यह सीट छोड़ दी थी। इस बार वह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) उम्मीदवार के तौर पर यहां से अपना भाग्य आजमाएंगी। पूर्णिया लोकसभा सीट पर दो बार जद(यू) सांसद रहे संतोष कुशवाहा को पराजित कर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने जीत दर्ज की। इस सीट पर भारती की जमानत जब्त हो गई थी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक दिन पहले भारती को पार्टी का चुनाव चिह्न दे दिया, लेकिन औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने रूपौली सीट से चुनाव लड़ा था। भाकपा ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वह उपचुनाव लड़ेगी।

श्रीनगर में प्रधानमंत्री मनाएंगे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून (शुक्रवार) को श्रीनगर में मनाएंगे, इस दौरान वह सभा को संबोधित करेंगे और एक योग सत्र कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी 20 और 21 जून को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में %एम्पावरिंग यूथ, ट्रांसफॉर्मिंग जेएंडके% कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू-कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बयान में कहा गया है कि वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना (जेकेसीआईपी) भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री 21 जून को सुबह लगभग 6ः30 बजे श्रीनगर के एसकेआईसीसी में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह इस अवसर पर सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री का यहां होना पूरी कश्मीर घाटी के लिए सम्मान की बात है।

उज्जवल निकम फिर से स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर नियुक्त

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव में असफल रहे अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को सरकारी वकील के रूप में फिर से नियुक्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले ने विवाद पैदा कर दिया है। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला प्रशासन गलत मिसाल कायम कर रहा है। मुंबई उत्तर-मध्य निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन से पहले जिन मामलों को वह संभाल रहे थे, उनमें निकम की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा, राज्य सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में भाजपा कार्यकर्ता को नियुक्त करने का विकल्प क्यों चुना है? भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी वकील के महत्वपूर्ण पद पर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को नियुक्त करके एक गलत मिसाल कायम की है। पटोले ने कहा कि शिंदे सरकार को निकम को दोबारा नियुक्त करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। भाजपा ने निवर्तमान सांसद पूनम महाजन को हटाकर निकम को इस सीट से मैदान में उतारा था। हालांकि, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने निकम को 16,514 वोटों के अंतर से हराया। गायकवाड़ को 445,545 वोट मिले.

पंजाब व दक्षिण में भाजपा के प्रदर्शन के मायने

उमेश चतुर्वेदी

चुनावी चर्चाओं के बीच एक बात पर कम ध्यान है। नतीजों में पिछड़ने के बावजूद भाजपा ने कुछ इलाकों में कुलांचें मारने में सफल भी हुई है। ओडिशा और तेलंगाना के नतीजों की इस संदर्भ में चर्चा हो भी रही है। लेकिन कम से कम तीन राज्य ऐसे हैं, जहां भाजपा का प्रदर्शन ध्यान खींचता है। पंजाब, केरल और तमिलनाडु में उसने बिना किसी बड़े सहारे के जो प्रदर्शन किया है, उससे विरोधियों को चिंतित होना चाहिए। दोबारा जब किसान आंदोलन उभरा था, तो हरियाणा पुलिस ने अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर पंजाब से आते आंदोलनकारी किसानों को रोका था, जो चर्चा का विषय बना था। किसान आंदोलन को लेकर मान लिया गया था कि पूरा पंजाब ही भाजपा के खिलाफ है। सीटों के लिहाज से नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन वोटों के लिहाज से उसने जबरदस्त उछाल मारा है। वाजपेयी की अगुवाई में बने एनडीए के जमाने से भाजपा पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के छोटे भाई की भूमिका में रही है। जालंधर, अमृतसर, पटियाला और लुधियाना जैसी शहरी सीटों पर ही वह अकाली दल के सहयोग से चुनाव लड़ती रही है। भाजपा की अपनी राजनीति को सीमित करने के अकाली प्रयास का पहला विरोध नवजोत सिद्धू ने किया। पर वे सफल नहीं हुए और उन्हें कांग्रेस में ठौर तलाशना पड़ा।

किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के राजनीतिक माहौल को देखते हुए अकाली दल ने भाजपा से अपनी अलग राह कर ली। इसके बाद भाजपा ने अपने दम पर आगे बढ़ने की सोची। अकालियों के सहयोग से 2019 में चुनाव लड़कर महज 9.63 प्रतिशत मत हासिल करने वाली भाजपा ने विपरीत हालात में 2024 में 18.56 प्रतिशत मत पाया है। पंजाब में पार्टी के बारे में कहा जाता रहा है कि वह शहरी हिंदुओं की पार्टी है। राज्य में हिंदू आबादी करीब 38.5 प्रतिशत है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को महज 25 और 26 प्रतिशत मत ही मिल सके हैं। बहुकोणीय मुकाबले के चलते कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने में सफल रही। जो अकाली दल भाजपा को अपना पिछलग्गू बनाने की कवायद में जुटा रहता था, उसे करीब 13 प्रतिशत से ही संतोष करना पड़ा। हां, उसे एक सीट मिली है।

कर्नाटक को छोड़ दें, तो दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भाजपा के लिए प्रश्न प्रदेश रहे हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों का दबदबा रहा है। अतीत में भाजपा को कभी सफलता मिली भी, तो उसे द्रविड़ पार्टी की खैरात माना गया। पर बिना किसी द्रविड़ राजनीतिक बैसाखी के सहारे पार्टी ने पहली बार 2024 में खुद की जमीन तैयार करने की सोची। अन्नामलाई की अगुआई में पार्टी 11 प्रतिशत से अधिक वोट पाने में सफल रही। राज्य की 39 में से महज 19 सीटों पर ही वह लड़ी थी और चार जगहों पर उसके सहयोगी दल उतरे। साल 2019 में पार्टी को यहां से महज 3.6 प्रतिशत वोट मिले थे। कांग्रेस इस बार के अपने प्रदर्शन को लेकर भाजपा पर खूब तंज कर रही है। तमिलनाडु में उसे सीटें मिलने का श्रेय गठबंधन को जाता है। लेकिन उसे वोट 10.78 प्रतिशत ही मिला है, जो भाजपा से कम है। तमिलनाडु से सटे केरल की त्रिशूर सीट पर भाजपा को जीत मिली है। पार्टी को 2019 में राज्य में करीब पंद्रह फीसदी वोट मिले थे, जो इस बार 20 प्रतिशत से ज्यादा है। अनेक सीटों पर उसका जबरदस्त प्रदर्शन रहा। दिलचस्प यह है कि केरल में भाजपा हिंदू समुदाय के बजाय ईसाई समुदाय में पैठ बनाती दिख रही है।

आंध्र प्रदेश में भाजपा की सफलता में तेलुगू देशम का सहयोग शामिल है। लेकिन तेलंगाना की कामयाबी उसकी अपनी है। वहां 2019 में पार्टी को 19.65 प्रतिशत वोट और चार सीटें मिली थीं, पर इस बार उसे 35.08 प्रतिशत वोट और आठ सीटें हासिल हुई हैं। यह बड़ी जीत है और वह यहां सत्ताधारी कांग्रेस से मुकाबला कर रही है। कुछ महीने पहले जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो नैरेटिव गढ़ा गया था कि उत्तर भारत के लोग जहां जाति और धर्म के आधार पर वोट डालते हैं, वहीं दक्षिण के लोग मुद्दों पर मतदान करते हैं। इस तरह भाजपा और उसके वोटरों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी। दक्षिण और पंजाब जैसे राज्य में भाजपा की बढ़त के संदर्भ में इसे सही माना जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश या बिहार में इंडिया गठबंधन को बेहतर नतीजे मिले हैं, तो क्या उस पर जाति और धर्म वाला नैरेटिव लागू नहीं होना चाहिए? राजनीतिक पंडितों और इंडिया गठबंधन को इस पर सोचना चाहिए।

बहरहाल, ओडिशा और तेलंगाना के नतीजों तथा पंजाब, तमिलनाडु और केरल में भाजपा की बढ़त का संदेश साफ है। भाजपा कांग्रेस की तरह अखिल भारतीय पार्टी बन चुकी है तथा वह विभिन्न समुदायों में भी पैठ बना रही है। भाजपा की बुनियाद हिंदुत्व है, जिसे वह भारतीयता का प्राण बिंदु मानती रही है। इसी बुनियाद पर वह आगे बढ़ रही है। विंध्य के नीचे के इलाकों में भी पहुंच रही है और हिमालय की तलहटी में भी। उत्तर-पूर्व में भी उसने पहले से ही धमक बना रखी है। चुनाव नतीजों को इन संदर्भों में भी देखा और समझा जाना चाहिए।

अदाणी समूह के सीमेंट प्लांट के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल की जनसुनवाई संपन्न

■ 99 प्रतिशत लोगों ने पक्ष में दिया अपना समर्थन

मस्तूरी। पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जिले के मस्तूरी ब्लॉक में प्रस्तावित अदाणी समूह की एसीसी सीमेंट प्लांट के लिए मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई सम्पन्न हो गई। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यावरण स्वीकृति के आदेश के लिए जनसुनवाई 18 जून 2024 को प्रात: 11:00 बजे से ग्राम लोहर्सी में आयोजित की गई। जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में बिलासपुर के अतिरिक्त कलेक्टर आरए कुरुवंशी तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी मनीष कश्यप मौजूद थे। परियोजना के बारे में जानकारी एसीसी सीमेंट, चिल्हाटी के खान प्रबंधक पिनाकपानी पांडे ने दी। जनसुनवाई लगभग 3 ।30 घंटे से ज्यादा समय तक चली। जिसमें पचपेड़ी तहसील के ग्राम लोहर्सी सहित गोदाडीह, बोहारडीह, भुरकुंडा, इत्यादि गांव के हजारों ग्रामीणों ने भाग लिया।

जनसुनवाई के दौरान सभा में ग्रामीणों द्वारा मुख्यरूप से क्षेत्र का विकास, भूमि का उचित मुआवजा, नौकरी और स्वरोजगार के लिए गांव से पलायन रोकने उचित प्रबंध सहित कई बातों तथा सुझावों को शांति पूर्वक रखा जिसे कुरवंशी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनकर जरूरी सुविधाओं को संबंधित कंपनी के अधिकारीयों की उपस्थिति में पूरा करने का भरोसा दिलाया।

ग्राम लोहर्सी की महिला ममता तिवारी ने जनसुनवाई के दौरान कहा कि, एसीसी आने के पहले इस गांव को कोई नहीं जानता और ना ही कोई विकास हो रहा था, लेकिन जब से इसका एसीसी खदान खुला है तब से कई विकासात्मक कार्य शुरू हो गए हैं। और अब एसीसी सीमेंट संयंत्र खुलने से हमारे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविकीय योजना इत्यादि के साथ साथ विकास के कार्य और भी ज्यादा होंगे। इसलिए मैं हमारे गांव में अदाणी समूह की एसीसी सीमेंट खुलने का समर्थन करती हूँ। इस तरह लोक सुनवाई में पधारे 99 फीसदी लोगों ने एसीसी सीमेंट संयंत्र खुलने का समर्थन किया। ग्राम लोहर्सी के सरपंच भानु प्रसाद ने जन सुनवाई के सफल होने पर खुशी जाहीर की।

जन सुनवाई के अंत में अदाणी सीमेंट के मुख्य विनिर्माण अधिकारी रामभव गट्टू ने जनसुनवाई में पधारे सभी ग्रामीणों को कंपनी के सामाजिक सरोकारों के माध्यम से हर तरफ विकासात्मक कार्य कराने की अपनी प्रतिबद्धता की बात कही साथ ही जनसुनवाई आयोजित कराने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पर्यावरण विभाग, सभी ग्रामीणजनों तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया।

असल में अदाणी एसीसी सीमेंट की जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम चिल्हाटी सहित लोहर्सी, विद्याडीह, गोडाडीह, बोहरडीह और भुरकुंडा में कई सालों से चुना पत्थर की खदानें मौजूद हैं। इसलिये मेसर्स अदाणी एसीसी लिमिटेड इनमें से तीन ग्राम गोदाडीह, बोहारडीह एवं लोहर्सी तहसील मस्तूरी, जिला- बिलासपुर में एकीकृत सीमेंट परियोजना, जिसकी क्लिंकर -3.3 मिलियन टन प्रति वर्ष, सीमेंट -1.0 मिलियन टन प्रति वर्ष, सीपीपी-30 मेगावाट, डब्ल्यूएचआरएस-17 मेगावाट और डीजी सेट-2×2000 केवीए और 1×500 केवीए प्रस्तावित है। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम चिल्हाटी को चूना पत्थर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो मस्तूरी से 30 किमी दूर स्थित है।

आईईडी ब्लास्ट से महिला बुरी तरह से जख्मी

बीजापुर। बीजापुर में नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला की बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी इलाज जारी है। आईईडी की चपेट में आने से महिला की दोनों पैर जख्मी हो गया है। साथ ही शरीर में भी कई चोट लगी है। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में आईईडी प्लांट किए थे। प्लांट की गई प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला के दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। जानकारी मिलने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह उसूर थाना क्षेत्र के नड़पल्ली निवासी बुजुर्ग महिला जोगी पति गंगा उम्र 55 जंगल में टोरा बिन रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने प्लांट की गई प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला के दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। साथ ही बुर्जुग महिला को शरीर के अन्य हिस्से में भी चोट पहुंची हैं।

बलौदाबाजार कांड, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा-

चुनाव में हार की खीझ निकालने कांग्रेस कर रही प्रोपोगेंडा

धमतरी। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू मंगलवार को पहली बार धमतरी पहुंचे। तोखन साहू कांकेर दौरे के लिए जाते हुए धमतरी में रुके। इस दौरान तोखन साहू ने बलौदाबाजार कांड पर कांग्रेस के धरने को प्रोपोगेंडा करार दिया है।

मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी की सरकार को तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। देश-विदेश में लोकप्रिय मोदी सरकार ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त डालने जा रही है। इसी के तहत कांकेर में कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें शामिल होने जा रहा हूं। तोखन साहू ने बलौदाबाजार घटना पर कांग्रेसियों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा हमला बोला है।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा आज से 6-7 महीने पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका। लोकसभा का चुनाव आया तब भी भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे। जनता ने भूपेश बघेल को वापस पाटन भेज दिया। चुनाव में हार की खीझ निकालने के लिए कांग्रेस इस तरह की प्रोपोगेंडा रच रही है।

प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर कसा तंज = केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने प्रियंका गांधी के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए इसे परिवारवाद करार दिया है। तोखन साहू ने कहा, कांग्रेस में परिवारवाद है, दूसरी कोई सोंच ही नहीं है कांग्रेस के पास।

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने कांकेर के दौरे पर निकले थे। इस बीच धमतरी पहुंचने पर शहर के घड़ी चौक में भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की गई। केंद्रीय राज्यमंत्री का स्वागत करने कलेक्टर-एसपी समेत व्यापारी संघ भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान पूर्व विधायक रंजना साहू, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस, भाजपा के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चारामा में धड़ल्ले से हो रहा अवैध रेत खनन, अधिकारी नहीं ले रहे एक्शन

■ ग्रामीण सड़कों पर उतरे

कांकेर। कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र में अवैध खनन का खेल जोरों पर है। प्रशासन के अधिकारियों के नाक के नीचे से खनन माफिया इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अधिकारी अवैध खनन रोकने में नाकाम हैं। इस वजह से रात के अंधेरे में चारामा क्षेत्र की महानदी के दर्जनों घाटों में धड़ल्ले से अवैध खनन का खेल चल रहा है और माफिया बेखौफ होकर रेत खनन की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।

अवैध खनन की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि चारामा क्षेत्र की महानदी से रेत से भरे ट्रक ले जाए जा रहे हैं। माहुद रेत खदान से हर दिन 200 से ट्रक निकलते हैं। भिरौदा, तेलगुड़ा, हारडुला खरथा, किलेपार, भिरौद में रात के अंधेरे में रेत का अवैध खनन का कारोबार हो रहा है।

एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि नदियों में किसी भी तरह की खुदाई नहीं होगी। यह आदेश 15 जून से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। एनजीटी के आदेशों के बावजूद प्रशासन व विभाग के अधिकारी आदेशों का पालन करवाने में ढीला रवैया अपना रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों की नर्मी की वजह से खनन माफिया खुलेआम खुलेआम रेत की खुदाई कर रहा है। क्योंकि उन्हें कोई रोकने -टोकने वाला नहीं है।

अवैध रेत खनन के विरोध में ग्रामीण रोष जता रहे हैं। मंगलवार रात को स्थानीय लोग मचांदुर नाके पर विरोध जताने पहुंते, तभी उनके सामने ही वहां से रेत से भरे आधा दर्जन ट्रक निकले। लोगों ने आरोप लगाया कि मचांदुर नाके पर खनिज विभाग के इंस्पेक्टर तैनात रहते हैं। रात के अंधेरे में ये भी अपनी आंखें बंद कर लेते है। राजनीतिक लोग और रेत माफिया एक सिंडिकेट बना कर पूरे चारामा क्षेत्र में अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने सुबह 5 बजे तक अपना विरोध जताया।

बलौदाबाजार हिंसा मामला : भीम आर्मी क्रांतिवीर का संस्थापक गिरफ्तार

स्पेशल पुलिस कर रही पूछताछ

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल पुलिस टीम ने आज बुधवार को भीम आर्मी क्रांतिवीर के संस्थापक किशोर नवरंगे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक जिले में हिंसा और न के बाद से ही किशोर नवरंगे फरार था। सूत्रों के मुताबिक नवरंगे ने ही 10 जून को धरना और रैली का आयोजन किया था और किशोर नवरंगे के ही आह्वान पर ही प्रदेश भर से समाज के लोग बलौदाबाजार पहुंचे थे। जिले में हिंसा भड़काने को लेकर पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है।

बता दें, 10 जून को बलौदाबाजार में भयानक हिंसक घटना हुई जिसमें उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में रखी सभी गाड़ियों में आग लगा कर खाक कर दिया। इतना ही नहीं, भयानक आगजनी में पूरी सरकारी बिल्डिंग भी धूं-धूं कर जल गईं। हालांकि, इस घटना के ठीक कुछ घंटों पहले ही उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मामले की न्यायिक जांच की घोषणा की थी, लेकिन इस हिंसक घटना को पूरे तैयारी के साथ बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने अंजाम दिया।

फिलहाल पुलिस किशोर नवरंगे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में पुलिस को प्रारंभ से ही आरोपी की तलाश थी और अब पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में अधिक जानकारी नहीं दी है और पूछताछ जारी है।

मंत्री नेताम ने 31 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अस्पताल का किया भूमिपूजन

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामनुजगंज जिला प्रवास के दौरान कृषि और आदिम जाति विभाग के मंत्री रामविचार नेताम ने जिले को स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। उन्होंने जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल और 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमिपूजन किया। लगभग 31 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाले यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जनता को संबोधित करता हुए कहा कि यह स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तारीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके बन जाने से जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। इन अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था के साथ मेडिकल केयर मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिले वासियों को पहुंच संबंधी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके पूर्ण हो जाने से लोगों को दूसरे स्थान पर इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तत्काल जरूरत पड़ने पर अब बलरामपुर जिले में ही बड़े अस्पतालों जैसी सुविधा मिलेगी। साथ ही इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

महिला बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बड़े-बड़े कार्य स्वीकृत हो रहे हैं उन्हीं के प्रयासों से स्वास्थ्य क्षेत्र में 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हेल्थ और मातृ एवं शिशु अस्पताल बनने जा रहा है इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगा। उन्होंने इसके लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नपं के प्रभारी सीएमओ सहित तीन उप अभियंता निलंबित

बिलासपुर। घरघोड़ा नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता के साथ नगर पंचायत के तत्कालीन उप अभियंता निखिल जोशी, प्रदीप पटेल और अजय प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने उनके खिलाफ मिली शिकायत को जांच में सही पाए जाने पर कार्रवाई की है। संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा गठित जांच समिति ने घरघोड़ा नगर पंचायत में अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सीसी रोड़ निर्माण कार्य का भुगतान करने और निजी व सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बगैर सीसी रोड़ निर्माण कार्य संपादित कराए जाने का दोषी पाया। समिति के प्रतिवेधन के आधार पर कार्रवाई किया गया।

पुरखती कागजात पुस्तक के मुद्रण हेतु 24 जून तक रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित

जगदलपुर। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण बस्तर संभाग द्वारा आदिवासी परम्परा, रीति-रिवाज, सांस्कृतिक विविधता एवं ऐतिहासिक विरासत को संवर्धन एवं संरक्षण करने के उद्देश्य से पुरखती कागजात नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा उक्त पुस्तक को आमजनों सहित साहित्यकारों, लेखकों और शोधकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए अधिकाधिक संख्या में प्रकाशक के माध्यम से मुद्रण कराए जाने हेतु उक्त पुस्तक का कापी राईट एवं मुद्रण का सर्वाधिकार प्रकाशक को दिया जाना है। इच्छुक प्रकाशकों से पुरखती कागजात (हिन्दी एवं अंग्रेजी) को मूल स्वरूप में मुद्रण एवं वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आगामी 24 जून 2024 को दोपहर 3 बजे तक रूचि की अभिव्यक्ति कार्यालय कमिश्नर एवं सदस्य सचिव बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण बस्तर संभाग जगदलपुर में आमंत्रित किया गया है।

कोरिया जिले से 102 श्रद्धालु करेंगे रामलला के दर्शन

कोरिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जिले के 102 श्रद्धालुओं को कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती वंदना राजवाड़े, जनपद पचायत अध्यक्ष बैकुण्ठपुर श्रीमती सौभाग्यवती कुसरो, गणमान्य नागरिक श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल ने तीर्थयात्रियों को पुष्प भेंट कर मंगलमय यात्री की शुभकानाएं दी एवं हरी झंड़ी दिखाकर अम्बिकापुर के लिए रवाना किया। दर्शनार्थी अम्बिकापुर रेल्वे स्टेशन से आस्था स्पेशल विशेष ट्रेन से दोपहर 12:00 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। श्रीरामलला दर्शन हेतु जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर ग्रामीण से 50 एवं सोनहत से 22, नगरपालिका बैकुण्ठपुर से 17, चरचा से 10 एवं 3 अनुरक्षक अधिकारी भेजे गए है। बता दें कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी।

राशनकार्ड नवीनीकरण 30 जून तक करवाने का आग्रह

जगदलपुर। जिले में प्रचलित 204698 राशनकार्डों में से 194113 (98.83 प्रतिशत) राशनकार्डों के नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा 10585 राशनकार्डों का नवीनीकरण होना शेष है। खाद्य विभाग द्वारा आगामी 30 जून 2024 तक राशनकार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाने के निर्देश दिये गए हैं। नवीनीकरण हेतु शेष राशन कार्डधारियों की दुकानवार सूची सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। नवीनीकरण हेतु शेष राशन कार्डधारी अपनी राशनकार्ड का नवीनीकरण स्वयं मोबाईल एप के माध्यम से कर सकते हैं अथवा उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर करवा सकते हैं। खाद्य अधिकारी द्वारा आग्रह किया गया है कि जिले के ऐसे राशन कार्डधारी जिनके द्वारा अभी तक अपने राशनकार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर अथवा स्वयं मोबाईल एप के माध्यम से 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से राशनकार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण करवाएं।

आपदा की स्थिति में 1070 आपतकालीन नम्बर जारी

नारायणपुर। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा सी-डेक, तिरूवनंतपुरम एवं राज्य सरकार के सहयोग से जन समुदाय को आपदा में त्वरित सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु ई.आर.एस.एस (डॉयल 1070-आपदा प्रबंधन आपतकालीन नम्बर) संचालित किया जा रहा है। जन समुदाय आपदा की स्थिति में सहायता हेतु ई.आर.एस.एस (डॉयल 1070-आपदा प्रबंधन आपतकालीन नम्बर) में संपर्क कर सकते हैं।

योग दिवस 21 जून को

21 जून 2024 को दशम् अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन क्रिड़ा परिसर खेल मैदान नारायणपुर में प्रात: 07 बजे से योग कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक सम्मिलित होंगे। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक विभाग के कार्यालय प्रमुख को अपने विभाग के अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ 21 जून को प्रात 06.30 बजे उपस्थित होने निर्देशित किया गया है।

खाली सरकारी जमीन पर रसूखदारों ने किया कब्जा

■ कार्रवाई करने से कांप रहे अधिकारियों के हाथ

बीजापुर। बीजापुर नगर के हृदय स्थल पर खाली पड़ी सरकारी जमीन पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया है। इस संबंध में मीडिया की ओर से ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

रसूखदारों ने आईटीआर भवन के पीछे स्थित खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वहां लगे सागौन और आम के पेड़ की कटाई कर दी। खसरा नंबर 969 के 0 ।0110 हेक्टेयर पर किए गए कब्जे वाली जमीन की कीमत करोड़ों में है। इस कवायद के लिए रसूखदारों ने पहले से ही शतरंत की बिसात बिछा चुके हैं। बताया जा रहा है कि रसूखदारों ने कब्जे से पहले पटवारी से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक की साठ-गांठ बना ली है।

जानकारों के मुताबिक, यह रसूखदारों के बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है, जिस पर भी कार्रवाई करने से प्रशासनिक अधिकारियों के कांप रहे हाथ-पांव अपने आप में बड़ा संदेश है। दरअसल, रसूखदार नेशनल हाइवे के दोनों ओर कब्जा जमाने की फिराक में है। इस कब्जे का फायदा हर लिहाज से है। लेकिन आलम यही रहा तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में मेन रोड़ किनारे किसी भी सरकारी भवन निर्माण के लिए जमीन नही बचेगी।

बीजापुर तहसीलदार डीआर ध्रुव ने मीडिया के सवाल पर बताया कि उन्होंने बीजापुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पत्र जारी कर दिया है। इस पूरे मामले पर बीजापुर फॉरेस्ट विभाग और बीजापुर राजस्व विभाग- दोनों टीमें मिलकर कार्रवाई करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन का बुरा हाल

सामुदायिक शौचालय में ग्रामीणों ने जड़े ताले

बेमेतरा। जिला में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करीब 550 गांव में समुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। इनमें से 250 शौचालयों के संचालन जिम्मा महिला समूहों को दिया गया है। परंतु इसका कोई उपयोग होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं देखरेख के अभाव में सामुदायिक शौचालय महज शो-पीस बनकर रह गए हैं।

शासन की ओर से गांव-गांव में समुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया था। ताकि लोग खुले में शौच करने से बचे और लोगों में जागरूकता आ सके। शासन की इस योजना को धरातल पर तो उतारा गया, परंतु इन शौचालयों का कोई उपयोग होता नजर नहीं आ रहा है। जिले के अधिकतर ग्राम पंचायतों में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों में ताला जड़ा हुआ है। जिसकी वजह से शैचालयों का उपयोग नहीं हो रहा है।

सीईओ, जिला पंचायत बेमेतरा टेकचंद अग्रवाल ने कहा मैंने बहेरा गांव का निरीक्षण किया है, जहां सामुदायिक शौचालय का बेहतर उपयोग हो रहा है। कई गांव में ताला जड़ने की शिकायत मिली है, जहां जनपद पंचायत के सीईओ और टीम को भेज कर लोगों को इसके उपयोग के प्रति जागरूक किया जाएगा।

कई ग्राम पंचायतों में जागरूकता के कमी की वजह सामुदायिक शौचालय केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। कुछ गांव में तो पानी के अभाव के चलते लोग सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने से बच रहे हैं। इसी वजह से कई गांवों में सामुदायिक शौचालय बंद पड़े हुए हैं।

शासन-प्रशासन को जागरूकता के कार्यक्रम चलाकर लोगों को सामुदायिक शौचालय के उपयोग करने के लिए जागरूक करना चहिए। ताकि लोगों को ओडीएफ के बारे में जागरूक किया जा सके। इससे लोग बेहिचक सामुदायिक शौचालयों का उपयोग करने लगेंगे।

संक्षिप्त समाचार

एनसीसी प्रशिक्षकों और कैडेट सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर

ग्रुप के एनसीसी प्रशिक्षकों और कैडेट सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नई दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल प्रशिक्षकों और कैडेट को सम्मानित किया। इसके अलावा नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नौ सेना, थल सेना और वायु सेना कैडेट भी पुरस्कृत हुए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद थे।

मुख्यमंत्री से भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में भारतीय पुलिस सेवा 75वें आरआर बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के निदेशक श्री रतनलाल डांगी ने बताया कि भारतीय पुलिस सेवा 75वें आरआर बैच के चार अधिकारियों श्री आकाश श्रीश्रीमाल, श्री अजय कुमार, श्री अक्षय प्रमोद साबरा और श्री विमल कुमार पाठक को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। इन अधिकारियों ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में 11 महीने व छत्तीसगढ़ में 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के रूप में आप के ऊपर सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण की अवधि का लाभ उठाकर निश्चित ही आप सभी बेहतर पुलिसिंग के मानदंडों पर खरे उतरेंगे। इस मौके पर राज्य पुलिस अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्री जयंत वैष्णव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल महासमुन्द के योग कार्यक्रम में होंगे शामिल

रायपुर। राज्य के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए मंत्रिमंडल, सांसद और विधायकों को नामांकित किया गया है। इसी तारतम्य में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महासमुन्द में आयोजित योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को नकली होलोग्राम केस में किया गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में

जमानत पर जेल से रिहा हुए अनवर ढेबर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 18 जून की देर रात नकली होलोग्राम केस में ढेबर गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान ढेबर के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया, मौके पर पुलिसबल ने भीड़ पर काबू पाया। यूपी एसटीएफ आज अनवर ढेबर को रायपुर कोर्ट में पेश किया है। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ ट्रांजिट रिमांड लेकर ढेबर को यूपी के मेरठ कोर्ट में पेश करेगी। शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ढेबर मंगलवार देर शाम ही वे जेल से रिहा हुए। इस दौरान मौके पर यूपी एसटीएफ ने होलोग्राम केस में ढेबर को पकड़ लिया। इस दौरान उसके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। साथ ही पुलिसबल के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। जैसे तैसे पुलिसबल ने भीड़ को शांत किया इसके बाद ढेबर को सिविल लाइन थाने ले जाया गया।

अग्रवाल महिला मंडल ने किया छाछ का वितरण

रायपुर। भीषण गर्मी को देखते हुए बुधवार

को रामसागर पारा - जवाहर नगर अग्रवाल महिला मंडल की सदस्यों ने जवाहर नगर के श्री शिव राधा कृष्ण मंदिर, राठौर चौक हनुमान मंदिर और चिकनी मंदिर गोलबाजार के सामने राहगिरों को 200 लीटर छाछ का वितरण किया। प्रचार प्रसार मंत्री ज्योति अग्रवाल ने बताया कि आगामी कार्यक्रम पर्यावरण पर होगा जहां वृहद स्तर पर पोधों का रोपण समाज के द्वारा किया जायेगा। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के महा मंत्री मनमोहन अग्रवाल, महिला मंडल प्रभारी कैलाश मुरारका, महिला मंडल की अध्यक्षा माया मुरारका, सचिव ममता अग्रवाल, संयोजिका बॉबी जैन, सह सेयोजिका ज्योत्सना अग्रवाल, संगठन मंत्री शशि अग्रवाल, मंत्री संजू अग्रवाल, मीना अग्रवाल, प्रचार प्रसार मंत्री ज्योति अग्रवाल, बृजलता अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, सपना अग्रवाल, रामसागरपारा - जवाहर नगर के संयोजक आयुष अग्रवाल, पूर्व संयोजक संजय अग्रवाल, किशन अग्रवाल के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सांसद अग्रवाल के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले- नहीं जाना चाहते हैं लोकसभा

मंत्रिमंडल में बृजमोहन सबसे सीनियर, बाकी मंत्री अनुभवहीन

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को केंद्रीय मंत्री मंडल में जगह न मिलने के बाद से लगातार कांग्रेस इस मामले पर मुखर नजर आ रहे हैं। उनके विधायक पद से इस्तीफे के बाद सियासत और तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता शुरू से यही चाहते थे कि बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा दे और उनके लिए जगह बन सके। बृजमोहन अग्रवाल की लोकसभा में जाने की खुद की इच्छा नहीं है। उनको अपने दिल की बात सुननी चाहिए।

भूपेश बघेल ने कहा, बृजमोहन अग्रवाल सीनियर नेता हैं। हमारे सबसे सीनियर विधायक हैं, मंत्री मंडल में वरिष्ठ हैं। अनुभवहीन लोग मंत्री बने हुए हैं। कम से कम एक आदमी तो अनुभवी रहे। बीजेपी के नेता तो चाहेंगे ही की बृजमोहन अग्रवाल जल्दी से इस्तीफा दें, क्योंकि एक पद पहले से खाली है फिर यह भी इस्तीफा देंगे तो दो पद खाली हो जाएंगे तो वह एडजस्ट हो सके, लेकिन अब देखना होगा कि बिल्ली के भाग में सिक्का कब फूटता है।

बलौदाबाजार घटना पर बोले- फिल्म देखने आए लोगों की हुई गिरफ्तारी

बलौदाबाजार की घटना को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि जब हम गए थे तो एक महिला मुंगेली की मिली थी। वह बता रही थी कि उनके पति फिल्म देखने आए थे उसको वहां से उठाकर ले गए हैं। वो कहां है इसका पता नहीं है। अभी हमारे और कुछ सतनामी समाज के साथी आए थे। वह बता रहे थे कि तीन लोग वहां पिक्चर देखने आए थे, उनको उठा लिया गया है। इनमें से दो बुजुर्ग थे इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। तीसरे व्यक्ति के साथ बहुत बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और वह कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है।

मॉब-लिंचिंग मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं?

आरंग मॉब-लिंचिंग मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस घटना में ओड़िशा की तरफ गाड़ी जा रही थी। बजरंग दल के लोगों ने गाड़ी को रोका, उसके बाद घटना हुई। इस घटना में दो लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी। तीसरे व्यक्ति की मृत्यु कल हुई है। यह 7 तारीख की घटना है, आज 19 तारीख है। अब तक एक भी अपराधी को इसमें पकड़ नहीं गया है। पुलिस भी इस पूरे मामले पर लीपापोती करने का काम कर रही है। यह बेहद दुर्भाग्य जनक है। जो अपराधी है उसे तत्काल पकड़ा जाना चाहिए। हमारे नेता आज वहां जा रहे हैं। पूरे घटना की जानकारी लेकर पीसीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

बीजेपी नेताओं के संरक्षण में हो रहा अवैध रेत उत्खनन : बघेल

छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है। बहुत सारे बीजेपी नेताओं के पार्टनरशिप में खदानें चल रही है तो इनको रोकेगा कौन? कल ही चरमा में ग्रामीणों ने हाइवा को रोका था, पुलिस आई, लेकिन न कोई कार्रवाई हुई न ही अब तक उस हाइवा की जब्ती बनाई। बीजेपी के छूट भैया नेता लोग गाढ़ी कमाई कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है।

'किसानों को बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार'

खाद-बीज को लेकर बघेल ने कहा, पूरे प्रदेश में खाद बीज की बड़ी किल्लत है। मेरे पाटन विधानसभा से भी ऐसी बातें सामने आ रही। प्रदेश में बीज की भी किल्लत है। अभी मैं बिलासपुर भी गया था तब भी स्वर्णा मसरी की डिमांड किसान कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसे उपलब्ध नहीं करवा पा रही है।

गरिमापूर्ण मनाया जाएगा योग दिवस

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विशेष पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इस साल भी देश-दुनिया के हर कोने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी उत्साह से योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आयोजन की भव्य तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय के मुख्य आतिथ्य में योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा। इसके अनुपालन में तैयारियों के लिए निर्देश विभिन्न विभागों को जारी किया गया है। इन निर्देशों के अनुपालन में तैयारियां आरंभ की जा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का कार्यक्रम राजधानी के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में विशेष रूप से होंगे। इनमें शासकीय के साथ ही अशासकीय संस्थाएं भी सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री ने पांच नि:शुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को मिल सकेगी स्वास्थ्य की आपातकालीन सुविधाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए 5 नि:शुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा संचालित नि:शुल्क एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर अब आठ हो गई है। क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को अब आपातकालीन सुविधा 24 घंटे 7 दिन मिलेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री केदार कश्यप और विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। विधायक श्रीमती भावना बोहरा की पहल से अपने एक और वादे को पूरा करने का हमें अवसर मिला है। नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौरी, पंडरिया, पांडातराई, दुल्लापुर एवं कुंडा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं आपातकालीन सेवा मिलेगी। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इससे किसी भी विषम परिस्थिति में मरीजों को त्वरित सेवा मिलेगी। जनहित के ऐसे प्रयास के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय भावना बोहरा की गारंटी सेवा संकल्प पत्र में हमने स्वस्थ एवं समृद्ध पंडरिया के उद्देश्य को सार्थक करने हेतु पंडरिया विधानसभा में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का संकल्प किया था और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सभी के सहयोग एवं समर्थन से हम अपने इस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं।

गौरतलब है कि रणवीरपुर एवं आदिवासी व वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर में पहले से ही तीन नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है और अब तक हजारों परिवारों को इस आपातकालीन सेवा का लाभ मिल रहा है। आपातकालीन समय में मरीजों को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर लाने-ले जाने के साथ ही बहुत से ऐसे मरीज थे, जिन्हें बेहतर उपचार हेतु रायपुर व अन्य जिलों में भी इस एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाने की सुविधा मिली है। इसके साथ ही पूर्व में संचालित एक नि:शुल्क मोबाइल हेल्थ पैथ लैब एवं महाविद्यालयीन छात्राओं हेतु महाविद्यालय से घर आने-जाने हेतु तीन नि:शुल्क बस सेवा की सुविधा दी जा रही है।

अब तेंदूपत्ता संग्रहण का नकद होगा भुगतान, हाट बाजार में लगेंगे कैप

सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों को मिलेगा लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री साय के निर्देशों के परिपालन में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में विभाग की ओर से बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब पारिश्रमिक राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। इन जिलों में हाट-बाजारों में कैंप लगाकर राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। तीनों जिलों में बैंकों की शाखाएं दूर-दूर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह निर्देश जारी किए हैं।

लाभार्थी किसानों को सहायता राशि का लाभ समय से मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने एक कारगर उपाय निकाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में दूरदराज के ट्राईबल एरिया में बैंक की शाखाएं दूर दूर होने के कारण तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले किसानों को उपज की खरीद के एवज में डायरेक्ट बैंक ट्रांस्फर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे पैसे का लाभ समय पर नहीं मिल पाता था। सरकार की ओर से बताया गया कि सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के तेंदूपत्ता संग्राहक किसानों को एक निश्चित समय तय करके उपज संग्रह के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए हाट-बाजारों में समय समय पर कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2024 में पारिश्रमिक राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की ओर से बताया गया कि विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलावा अन्य जिलों में तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके खाते में पारिश्रमिक राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से ही किया जाएगा। तेंदूपत्ता संग्रहण का नकद भुगतान जिला कलेक्टर की निगरानी में किया जाएगा।

राव ने बताया कि नकद भुगतान के लिए पात्र किसानों का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक पात्र किसान का नकद भुगतान कलेक्टर की अनुमति से होगा। इसके लिए इन तीनों जिलों में कलेक्टर, वन मंडल अधिकारी एवं प्रबंध संचालक द्वारा आपसी समन्वय से प्रस्तावित क्षेत्र के अंतर्गत हाट बाजार या अन्य उपयुक्त स्थान पर कैंप लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने बच्चों को दिया सिकल सेल जेनेटिक कार्ड, अब कहीं भी करा सकेंगे इलाज

- **स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के रुके वेतन जल्द होंगे जारी, मंत्री श्यामबिहारी ने की घोषणा**

रायपुर। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर रायपुर के अटल बिहारी वाजपई ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जयसवाल समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के रुके हुए वेतन जल्द जारी होंगे।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आयोजित सिकल सेल की स्क्रीनिंग और जागरूकता के लिए राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सीएम साय ने बच्चों को सिकल सेल

जेनेटिक कार्ड दिया। अब सिकल सेल जेनेटिक कार्ड के माध्यम से कहीं भी इलाज करा सकेंगे। हलबी और गोंडी में अनुवादित सिकल सेल की पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य विभाग के रुके हुए वेतन जल्द जारी होंगे। ऑनलाइन वेतन जारी करने सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर कर्मचारियों के रुके वेतन जारी हो जाएंगे।

टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण पहल

वन मंत्री ने अचानकमार टाइगर रिजर्व में चीतल छोड़ने हेतु रेस्क्यू वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित नंदनवन जू एवं सफारी का दौरा किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने नंदनवन जू एवं सफारी से चीतल को अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी, बिलासपुर छोडने हेतु रेस्क्यू वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जंगल सफारी से कुल 150 की संख्या में हिरणों को अचानकमार टाइगर रिज़र्व में छोडने की अनुमति मिली है, उसी अनुक्रम में आज पहली बार कुल 42 हिरण को रवाना किया गया है ।

वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने जंगल सफारी में भ्रमण पश्चात वन विभाग के अधिकारियों के साथ जंगल सफारी की आगामी कार्य योजना के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जंगल सफारी में नवीन सुविधाओं और विभिन्न गतिविधियों को जोडने पर विशेष जोर दिया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने भ्रमण के दौरान नंदनवन जू एवं सफारी के प्रयासों की सराहना की और अचानकमार में प्रे बेस

बढ़ाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया द्य चीतलों के स्थानांतरण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के सुरक्षित आवास और उनके संरक्षण के लिए इस प्रकार की ट्रांसलोकेशन गतिविधियां आवश्यक हैं। अचानकमार टायगर रिजर्व अपने समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। टाइगर रिज़र्व में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रे बेस बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।

वनमंत्री श्री कश्यप ने पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इनमें जंगल सफारी स्थित बॉटनिकल गार्डन का आकर्षण बढ़ाने सहित फिश एक्वेरियम की स्थापना आदि के सम्बंध में निर्देशित किया। इसी तरह जंगल सफारी में पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फाइबर टॉप बसों को अत्याधुनिक ढंग से सुसज्जित करने और वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। वनमंत्री के निर्देशों के अनुरूप उक्त सभी निर्माण कार्यों के लिए 31 जुलाई तक की समयसीमा निर्धारित की गई है।

महतारी वंदन योजना आर्थिक सशक्ति से परिवार में बढ़ा सम्मान, लक्ष्मी की बदल रही तकदीर

जून माह में चतुर्थ किस्त के रूप में 50 करोड़ 93 लाख 36 हजार 900 महिलाओं के बैंक खाते में जारी किए गए हैं

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का मूल उद्देश्य अब कारगर होता दिखाई दे रहा है। आर्थिक मजबूती से परिवार सम्पन्न हो रहा है और महिलाओं के जो सपने थे, वे अब साकार होने लगे हैं। रायपुर की श्रीमती लक्ष्मी फुटान ने सपना संजोया था, लेकिन आर्थिक तंगहाली की वजह से सपने अब तक पूरा नहीं कर पाई थी, महतारी वंदन योजना से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है।

श्रीमती लक्ष्मी घर का कामकाज संभालती है। उनके पति श्री गोपाल फुटान रोजी-मजदूरी करते है। श्रीमती लक्ष्मी बताती हैं कि पति की कमाई घरेलु खर्च पर ही इस्तेमाल हो जाता है। छोटी-मोटी जरूरतों की चीज भी खरीदने में काफी परेशानियां होती है, लेकिन अब जरूरतें भी पूरी होने लगी हैं। योजना की राशि का इस्तेमाल घर के खर्च में भी होता है और बचत भी कर रही है। क्योंकि भविष्य भी सुरक्षित हो सकेगा। यह दौर भी ऐसा आया है कि हाथ में पैसे होने से परिवार में भरपूर सम्मान मिल रहा है। वे बताती है कि सोने-चांदी के जेवर पहनने का मन काफी समय से है, लेकिन माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे वे जेवर खरीद सके। अब सपने पूरा करने के लिए वे प्रतिमाह बैंक अकाउंट में योजना से मिलने वाली राशि को इकट्ठे कर रही है। जिससे वे जेवर की खरीदी कर सके। श्रीमती लक्ष्मी यह भी कहती है कि बहुत खुशी होती है कि घर में बैठकर इतनी राशि मिल रही है। उनके दो बच्चे टीकम

और धनेंद्र के भविष्य की चिंता भी थी, हमेशा यही लगता था कि मैं भी थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कुछ काम करूं, पर राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना का मिलने से सही समय पर राशि प्रतिमाह मिल जाता है। उस पैसे की बचत कर बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर रही हूं। साथ ही अब घर की छोटी-मोटी चीजों को खरीदने के लिए पति पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ घरेलु खर्च होता है तो खुद पूरा कर लेती है। अब ज्यादा निर्भरता नहीं रहती है।

श्रीमती लक्ष्मी कहती है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मेरे जैसे लाखों महिलाओं को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते है। वे यह भी बताती है कि खान-पान भी बेहतर होता जा रहा है। राशन और घर की अन्य चीजें भी खरीदने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सशक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है और बेहतर पोषण से जीवन भी बेहतर होगा और परिवार भी स्वस्थ रहने के साथ खुशहाल भी रहेगा। जीवन में उत्तरोतर विकास से समृद्धि भी आएगी। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है।महिलाएं खुश है कि वो महतारी वंदन योजना से मिली राशि से अपने बच्चों और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी कर पा रहीं हैं साथ ही कई महिलाएँ भविष्य के लिए निवेश भी कर रहीं हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि उनका प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। इसी लिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 10 मार्च से प्रथम किश्त महिलाओं के बैंक खाते में भेजने से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना में रायपुर जिले के कुल 5 लाख 29 हज़ार 75 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिनको जून माह में चतुर्थ क़िस्त के रूप में 50 करोड़ 93 लाख 36 हज़ार 9 सौ रुपए महिलाओं के बैंक खाते में ज़ारी किए गए हैं।

आकार के अवसाद से उबरी कांग्रेस की चुनौतियां

राजेश बादल

लोकसभा चुनाव के बाद की कांग्रेस अपने नए अवतार में नजर आ रही है। पार्टी का अनमनापन, अनिर्णय की आदत और अलसाया चेहरा नहीं दिखाई देता। भारत का सबसे पुराना दल अंगड़ाई ले रहा है। पार्टी कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। इससे समाज के प्रबुद्ध मतदाताओं का बड़ा वर्ग राहत की सांस ले रहा है। लोकसभा में लगभग सौ कुर्सियों पर बैठने के अधिकार से यह बदलाव आया है। अपने बूते पर करीब सौ संसदीय सीटें और प्रतिपक्ष के अन्य सहयोगी दलों की लगभग एक सौ चालीस सीटें सरकार की नाक में दम करने के लिए पर्याप्त हैं। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल का बड़ा महत्व है। यह संख्या सरकार के किसी भी निर्णय के सामने पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी कर सकती है। वह दौर चला गया, जब प्रतिपक्ष में अकेले राम मनोहर लोहिया समूची सरकार को परेशानी में डाल दिया करते थे या फिरोज गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडीस, चंद्रशेखर, सोमनाथ चटर्जी और इंद्रजीत गुप्त जैसे राजनेताओं की सदन में उपस्थिति मात्र से सरकार या सत्ता पक्ष खौफ खाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज प्रत्येक पार्टी के नेता को अपने पीछे सिर्फ चेहरे नजर आते हैं। विपक्ष की बेंचों पर बढ़ती संख्या एक तरह से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है। फिलहाल हम सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। चूंकि कांग्रेस 2019 का चुनाव शर्मनाक ढंग से हारी थी। देश ने इस वयोवृद्ध पार्टी को फिसलते हुए इतिहास के सबसे निचले पायदान पर देखा था। अब उससे नीचे जाने का कोई कारण पार्टी और मतदाताओं की समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने पराजय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस जैसे ठिठक गई। वह एक तरह से सुसुप्तावस्था में चली गई थी। हालांकि राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद कांग्रेस ने तीन प्रदेशों में सरकारें बनाई थीं और अनेक उपचुनाव भी जीते थे। इस तरह से अध्यक्ष के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेने का कोई ठोस कारण नहीं बनता था। (वैसे भी मौजूदा राजनीति में नैतिक आधार पर त्यागपत्र का सिलसिला गुजरे जमाने की बात हो गई है।) क्योंकि वर्तमान सियासत में पराजय का अर्थ जनाधार खो देना नहीं होता और फिर पार्टी यदि पहले ही विपक्ष में बैठी हो तो इस्तीफे की कोई वजह नहीं बनती। यदि सरकार चला रही पार्टी बहुमत खो दे अथवा हार जाए तो ही एक तरह से त्यागपत्र का कारण माना जा सकता है। बहरहाल, कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं पा सकी थी। यह बेहद कड़वी और शर्मनाक स्थिति थी। राहुल गांधी के त्यागपत्र के बाद किंकर्तव्यविमूढ़ दल लंबे समय तक ऊहापोह से नहीं उबरा। इसी बीच महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य प्रदेशों के चुनाव भी निकल गए और पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद ही कांग्रेस जैसे नींद से जागी। पार्टी ने बाकायदा अपने संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया और अरसे बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा चुना हुआ अध्यक्ष कांग्रेस को मिला। इसी बीच राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान कर दिया। इसके बाद तो पांसा जैसे पलट गया। लोगों ने राहुल की यात्रा को भारी समर्थन दिया। उसके सकारात्मक परिणाम कर्नाटक और तेलंगाना में मिले। लोकसभा चुनाव आते-आते उत्तर प्रदेश ने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पसंद किया और अब हम पाते हैं कि लोकसभा में विपक्ष का नेता पद कांग्रेस की झोली में है। इस पद के कारण भाजपा सरकार के लिए कई मामलों में प्रतिपक्ष को साथ लेना आवश्यक हो जाएगा। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने और प्रियंका गांधी ने चुनावी राजनीति में उतरने का निर्णय किया।

लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव

नीरज कुमार दुबे

18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। दूसरी ओर विपक्ष भी इस प्रयास में है कि अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा जाये। विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह उपाध्यक्ष का पद उसे दे लेकिन सरकार इस मूड़ में नहीं दिख रही है कि इन दोनों पदों में से कोई भी पद विपक्ष को दिया जाये। इसलिए माना जा रहा है कि 18वीं लोकसभा का सत्र हंगामेदार हो सकता है। हालांकि, राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि अब तक लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन आम सहमति से ही हुआ है। इसलिए विपक्ष अगले सप्ताह लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार उतारकर यदि चुनाव की स्थिति उत्पन्न करता है तो यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी का चयन चूंकि हमेशा आम सहमति से होता रहा है इसलिए यदि यह परम्परा इस बार टूटती है तो यह एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी।

हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता से पहले संसद को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था और इसके अध्यक्ष पद के लिये पहली बार चुनाव 24 अगस्त 1925 में हुआ था जब स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार विट्ठलभाई जे. पटेल ने टी. रंगाचारियर के खिलाफ यह चुनाव जीता था। अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले गैर-सरकारी सदस्य विट्ठलभाई जे. पटेल ने दो वोटों के मामूली अंतर से पहला चुनाव जीता। पटेल को 58 वोट मिले थे, जबकि टी. रंगाचारियार को 56 वोट मिले थे। केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए 1925 से 1946 के बीच छह बार चुनाव हुए। विट्ठलभाई पटेल अपना पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद 20 जनवरी 1927 को सर्वसम्मति से पुन: इस पद पर निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा के आह्वान के बाद पटेल ने 28 अप्रैल, 1930 को पद छोड़ दिया। सर मुहम्मद याकूब (78 वोट) ने

नौ जुलाई, 1930 को नंद लाल (22 वोट) के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव जीता। याकूब तीसरी विधानसभा के आखिरी सत्र के लिए इस पद पर रहे। चौथी विधानसभा में सर इब्राहिम रहीमतुल्ला (76 वोट) ने हरि सिंह गौर के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव जीता, जिन्हें 36 वोट मिले। स्वास्थ्य कारणों से 7 मार्च 1933 को रहीमतुल्ला ने इस्तीफा दे दिया और 14 मार्च 1933 को सर्वसम्मति से षणमुखम चेट्टी उनके स्थान पर नियुक्त हुए। सर अब्दुर रहीम को 24 जनवरी 1935 को पांचवीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। रहीम को 70 वोट मिले थे, जबकि टी.ए.के. शेरवानी को 62 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। रहीम ने 10 साल से अधिक समय तक उच्च पद संभाला क्योंकि पांचवीं विधानसभा का कार्यकाल समय-समय पर प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तनों और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ाया गया था।

केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए अंतिम मुकाबला 24 जनवरी, 1946 को हुआ था, जब कांग्रेस नेता जी.वी. मावलंकर ने कावसजी जहांगीर के खिलाफ तीन मतों के अंतर से चुनाव जीता था। मावलंकर को 66 मत मिले थे, जबकि जहांगीर को 63 मत मिले थे। इसके बाद मावलंकर को संविधान सभा और अंतरिम संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद अस्तित्व में आई। मावलंकर 17 अप्रैल, 1952 तक अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने रहे, जब पहले आम चुनावों के बाद लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया।

स्वतंत्रता के बाद से लोकसभा अध्यक्षों का चयन सर्वसम्मति से किया जाता रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केवल एमए अयंगर, जीएस ढिल्लों, बलराम जाखड़ और जीएमसी बालयोगी ही बाद की लोकसभाओं में प्रतिष्ठित पदों पर पुन: निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अयंगर वर्ष 1956 में मावलंकर की मृत्यु के बाद अध्यक्ष चुने गये थे। उन्होंने 1957 के आम चुनावों में जीत हासिल की और उन्हें दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। ढिल्लों को 1969 में अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी के इस्तीफे के बाद चौथी लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। ढिल्लों को 1971 में पांचवीं लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना गया और वे 1 दिसंबर 1975 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने आपातकाल के दौरान यह पद छोड़ दिया था।

इसके अलावा, बलराम जाखड़ सातवीं और आठवीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे और उन्हें दो पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र पीठासीन अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है। बालयोगी को 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया, जिसका कार्यकाल 19 महीने का था। उन्हें 22 अक्टूबर 1999 को 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना गया। बालयोगी की 3 मार्च 2002 को एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पिछली लोकसभा में भाजपा सांसद ओम बिरला अध्यक्ष थे। इस बार वह अध्यक्ष बनेंगे या नहीं इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक बात साफ है कि अध्यक्ष पद भाजपा के पास ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष के मुद्दे पर सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाने का काम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा हुआ है और माना जा रहा है कि एकाध दिन में इस मुद्दे पर स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी। दूसरी ओर, विपक्ष भी कमर कस चुका है। दरअसल लोकसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत से उत्साहित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' अब आक्रामक तरीके से उपाध्यक्ष के पद की मांग कर रहा है, जो परंपरागत रूप से विपक्षी दल के सदस्य के पास होता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, यदि सरकार विपक्ष के नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत नहीं होती है तो हम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे।

हम आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा, जिस दौरान निचले सदन के नए सदस्य शपथ लेंगे और अध्यक्ष का चुनाव होगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में 'इंडिया' ने 234 सीटें जीतीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग ने 293 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी। 16 सीटों के साथ तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और 12 सीटों के साथ जनता दल (यू) भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी हैं। भाजपा ने 240 सीटें जीती हैं। जद (यू) ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है, जबकि तेदेपा ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार का समर्थन किया है। हालांकि विपक्षी गठबंधन तेदेपा पर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जोर देने या पार्टी में धीरे-धीरे विघटन का सामना करने के लिए कह रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

सुबालोपनिषद् (भाग-14)

गतांक से आगे...

यह श्वेत, विज्ञान को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है। यह विज्ञान, तुरीय को प्राप्त करता है, इस कारण यह मृत्युरहित, भयरहित, अशोक, अनन्त एवं अबीज तुरीय को ही प्राप्त होता है।

(इस प्रकार कहने के बाद पुन: उन्होंने कहना शुरू किया कि) जो चित्त को प्राप्त कर लेता है, वह चित्त में ही विलीन हो जाता है। यह चित्त, चिन्तन योग्य को पा लेता है, इस कारण यह चिन्तन करने योग्य में ही लय हो जाता है। यह चिन्तन करने योग्य, क्षेत्रज्ञ को प्राप्त कर लेता है, इस कारण इसका विलय क्षेत्रज्ञ में ही होता है।

यह क्षेत्रज्ञ, भास्वती नाड़ी में गमन कर जाता है, इस कारण यह भास्वती नाड़ी में ही विलीन हो जाता है। यह भास्वती, नाग वायु के पास जाती है, इस कारण यह नाग वायु में ही अस्त हो जाती है। यह नाग वायु, विज्ञान की ओर जाती है, इस कारण यह विज्ञान में विलय हो जाती है।

यह विज्ञान, आनन्द को प्राप्त कर लेता है, इस कारण यह आनन्द में ही विलीन हो जाता है और वह आनन्द मृत्युरहित, भयरहित, अशोक, अनन्त एवं निर्बीज तुरीय में जाता है, इस कारण से यह तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है।

(उन घोराङ्गिरस जी ने पुन: कहा कि) जो भी मनुष्य इस तरह से निर्बीज रूपी तत्त्व को जान लेता है, वह निर्बीज हो जाता है।

वह अजन्मा हो जाता है, मृत्यु एवं मोह को भी नहीं प्राप्त करता। उसका भेदन नहीं होता, जलता भी नहीं, छेदा भी नहीं जाता, कम्पायमान भी नहीं होता तथा कुपित भी नहीं होता है। इस प्रकार सभी कुछ दग्ध करने वाली यह आत्मा ही है, ऐसा शास्त्रवेत्ताओं का मत है।

क्रमश: ...

शरणार्थियों के प्रति जनता व प्रशासन को जागरूक करता है विश्व शरणार्थी दिवस

अमृता गोस्वामी

शरणार्थी वह लोग होते हैं जो हिंसा, संघर्ष, युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप जैसी मुसीबतों के चलते असहाय, लाचार और निराश्रय होकर अपने देश और घरों को छोड़कर किन्ही अन्य देशों में शरण लेने पर मजबूर हुए हों। 'विश्व शरणार्थी दिवस' ऐसे ही विस्थापित लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प को प्रतिष्ठित करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थियों को अंग्रजी भाषा में 'रिफ्यूजी' कहा जाता है।

आपदा-विपदा से ग्रसित कोई एक व्यक्ति भी शरणार्थी हो सकता है और बहुत सारे लोगों का समूह भी। सीरिया में हुई जंग तो आपको याद ही होगी जिसके चलते वहां के लाखों लोगों को अन्य देशों

की शरण में जाना पड़ा। भारत की बात करें तो यहां काफी संख्या में तिब्बत और बांग्लादेश से आए शरणार्थी आपको मिल जाएंगे। म्यांमार, लीबिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान, यूनान, मलेशिया व कई अफ्रीकी देशों से भी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में नागरिक अन्य देशों में शरणार्थी बनकर पहुंचते हैं। वेनेजुएला जैसे देश में आर्थिक संकट के चलते नागरिक को मजबूरीवश दूसरे देशों की शरण लेना पड़ रहा हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में शरणार्थियों की संख्या 6.56 करोड़ से भी ज्यादा है।

शरणार्थियों के जीवन-यापन, उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य तथा अन्य जरूरतों के लिए कई देशों में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएचसीआर (यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज़ी) एक ऐसी ही संस्था है जो शरणार्थियों की मदद के लिए, उन्हें कानूनी हक दिलाने और उन्हें पुन: अपना जीवन बसर करने के प्रति उपयुक्त हल तलाशने में उनकी सहायता करती है। इस कार्य के लिए यूएनएचसीआर को 1954 व 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

गौरतलब है कि अफ्रीकी देशों की एकता को अभिव्यक्त करने के लिये 4 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी (ओएयू) अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस को अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के साथ 20 जून को मनाने के लिये सहमत हुआ था, उसके बाद 2001 से प्रतिवर्ष दुनिया भर में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है।

इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व शरणार्थी दिवस पर कई गतिविधियाँ आयोजित करते हैं जिनमें शरणार्थी स्थलों का निरीक्षण करना, उनकी समस्याओं से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन करना, गिरफ्तार शरणार्थियों की मुक्ति के लिये विरोध प्रदर्शन तथा जेल में बंद शरणार्थियों के लिये समुचित चिकित्सकीय सुविधा और नैतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिये रैलियों का आयोजन करना जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

समर्थकों की भीड़ के बावजूद तन्हा हैं राहुल गांधी

फिरदौस खान

राहुल गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे देश और राज्यों में सबसे लम्बे अरसे तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से लाखों मतों से जीत हासिल कर इतिहास रचा है। उन्होंने अपने पुराने लोकसभा क्षेत्र वायनाड छोड़कर रायबरेली से सांसद रहने का फ़ैसला किया है। बहरहाल, उनकी ज़िन्दगी कोई आसान नहीं है। इसमें जितने फूल हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख़ार हैं जिनकी चुभन उन्हें हमेशा महसूस होती रहती है।

राहुल गांधी एक ऐसे ख़ानदान के वारिस हैं, जिसने देश के लिए अपनी जानें तक क़ुर्बान कर दीं। उनके भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में लाखों-करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन इस सबके बावजूद वे अकेले खड़े नज़र आते हैं। उनके चारों तरफ़ एक ऐसा अनदेखा दायरा है, जिससे वे चाहकर भी बाहर नहीं आ पाते। एक ऐसी दीवार है, जिसे वे तोड़ नहीं पा रहे हैं। वे अपने आसपास बने ख़ोल में घुटन तो महसूस करते हैं, लेकिन उससे निकलने की कोई राह, कोई तरकीब उन्हें नज़र नहीं आती।

बचपन से ही उन्हें ऐसा माहौल मिला, जहां अपने-पराये और दोस्त-दुश्मन की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया था। उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी का बेरहमी से क़त्ल कर दिया गया। इन हादसों ने उन्हें वह दर्द दिया, जिसकी ज़रा-सी भी याद उनकी आंखें भिगो देती है। उन्होंने कहा था- उनकी दादी को उन सुरक्षा गार्डों ने मारा, जिनके साथ वे बैडमिंटन खेला करते थे।

वैसे राहुल गांधी के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। कभी उन्हें जान से मार देने की धमकियां मिलती हैं, तो कभी उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके जाते है। अप्रैल 2018 में उनका जहाज़ क्रैश होते-होते बचा। कर्नाटक के हुबली में उड़ान के दौरान 41 हज़ार फ़ुट की ऊंचाई पर जहाज़ में तकनीकी ख़राबी आ गई और वह आठ हज़ार फ़ुट तक नीचे आ गया। उस वक़्त उन्हें लगा कि जहाज़ गिर जाएगा और उनकी जान नहीं बचेगी। लेकिन न जाने किनकी दुआएं ढाल बनकर खड़ी हो गईं और हादसा टल गया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ साज़िश

रचने का इल्ज़ाम लगाया था।

किसी अनहोनी की आशंका की वजह से ही राहुल गांधी हमेशा सुरक्षाकर्मियों से घिरे रहे हैं, इसलिए उन्हें वह ज़िन्दगी नहीं मिल पाई, जिसे कोई आम इंसान जीता है। बचपन में भी उन्हें गार्डन के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की इजाज़त नहीं थी। खेलते वक़्त भी सुरक्षाकर्मी किसी साये की तरह उनके साथ ही रहा करते थे। वे अपनी ज़िन्दगी जीना चाहते थे, एक आम इंसान की ज़िन्दगी। राहुल गांधी ने एक बार कहा था- अमेरिका में पढ़ाई के बाद मैंने जोखिम उठाया और अपने सुरक्षा गार्डो से निजात पा ली, ताकि इंग्लैंड में आम ज़िन्दगी जी सकूं। लेकिन ऐसा ज़्यादा वक़्त तक नहीं हो पाया और वे फिर से सुरक्षाकर्मियों के घेरे में क़ैद होकर रह गए।

हर वक़्त कड़ी सुरक्षा में रहना, किसी भी इंसान को असहज कर देगा, लेकिन उन्होंने इसी माहौल में जीने की आदत डाल ली। ख़ौफ़ के साये में रहने के बावजूद उनका दिल मुहब्बत से सराबोर है। वे एक ऐसे शख़्स हैं, जो अपने दुश्मनों के लिए भी दिल में नफ़रत नहीं रखते। वे कहते हैं- मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि नफ़रत पालने वालों के लिए यह जेल होती है। मैं उनका आभार जताता हूं कि उन्होंने मुझे सभी को प्यार और सम्मान करना सिखाया। अपने पिता की सीख को उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में ढाला, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के क़ातिलों तक को माफ़ कर दिया। उनका कहना है- वजह जो भी हो, मुझे किसी भी तरह की हिंसा पसंद नहीं है। मुझे पता है कि दूसरी तरफ़ होने का मतलब क्या होता है, ऐसे में जब मैं हिंसा देखता हूं चाहे वो किसी के भी साथ हो रही हो, मुझे पता होता है कि इसके पीछे एक इंसान, उसका परिवार और रोते हुए बच्चे हैं। मैं ये समझने के लिए काफ़ी दर्द से होकर गुज़रा हूं। मुझे सच में किसी से नफ़रत करना बेहद मुश्किल लगता है।

उन्होंने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (लिट्टे) के प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण का ज़िक्र करते हुए कहा था- मुझे याद है जब मैंने टीवी पर प्रभाकरण के मुर्दा जिस्म को ज़मीन पर पड़ा देखा। ये देखकर मेरे मन में दो जज़्बे पैदा हुए। पहला ये कि ये लोग इनकी लाश का इस तरह अपमान क्यों कर रहे हैं और दूसरा मुझे प्रभाकरण और उनके परिवार के लिए बुरा महसूस हुआ।

राहुल गांधी एक ऐसी शख़्सियत के मालिक हैं, जिनसे कोई भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता। देश के प्रभावशाली राज घराने से होने के बावजूद उनमें ज़रा भर भी ग़ुरूर नहीं है। उनकी भाषा में मिठास और अपनापन है, जो सभी को अपनी तरफ़ आकर्षित करता है। वे विनम्र इतने हैं कि अपने विरोधियों के साथ भी सम्मान से पेश आते हैं, भले ही उनके विरोधी उनके लिए कितनी ही तल्ख़ भाषा का इस्तेमाल क्यों न करते रहें. किसी भी हाल में वे अपनी तहज़ीब से पीछे नहीं हटते। उनके कट्टर विरोधी भी कहते हैं कि राहुल गांधी का विरोध करना उनकी पार्टी की नीति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ज़ाती तौर पर वे राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं। वे ख़ुशमिज़ाज, ईमानदार, मेहनती, क्षमाशील और सकारात्मक सोच वाले हैं। बुज़ुर्ग उन्हें स्नेह करते हैं, उनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखते हैं, उन्हें दुआएं देते हैं। वे युवाओं के चहेते हैं। राहुल गांधी अपने विरोधियों का नाम भी सम्मान के साथ लेते हैं, उनके नाम के साथ जी लगाते हैं। सच है कि संस्कार विरासत में मिलते हैं, संस्कार घर से मिला करते हैं। अपने से बड़ों के लिए उनके दिल में सम्मान है, तो बच्चों के लिए प्यार-दुलार है। वे इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं। अपने पिता की ही तरह अपने कट्टर विरोधियों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहते।

राहुल गांधी छल और फ़रेब की राजनीति नहीं करते। वे कहते हैं- %%मैं गांधीजी की सोच से राजनीति करता हूं। अगर कोई मुझसे कहे कि आप झूठ बोल कर राजनीति करो, तो मैं यह नहीं कर सकता। मेरे अंदर ये है ही नहीं। इससे मुझे नुक़सान भी होता है। मैं झूठे वादे नहीं करता। वे ये भी कहते हैं- सत्ता और सच्चाई में फ़र्क़ होता है। ज़रूरी नहीं है, जिसके पास सत्ता है उसके पास सच्चाई है। वे कहते हैं- जब भी मैं किसी देशवासी से मिलता हूं। मुझे सिर्फ़ उसकी भारतीयता दिखाई देती है। मेरे लिए उसकी यही पहचान है। अपने देशवासियों के बीच न मुझे धर्म, ना वर्ग, ना कोई और अंतर दिखता है।

कहते हैं कि सच के रास्ते में मुश्किले ज़्यादा आती हैं और राहुल गांधी को भी बेहिसाब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बचपन से ही उनके विरोधियों ने उनके ख़िलाफ़ साज़िशें रचनी शुरू कर दी थीं। उन पर लगातार ज़ाती हमले किए जाते हैं। इस बात को राहुल गांधी भी बखूबी समझते हैं, तभी तो एक बार विदेश जाने से पहले उन्होंने एक्स पर अपने विरोधियों को सम्बोधित करते हुए लिखा था- कुछ दिन के लिए देश से बाहर रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी के दोस्तों, ज़्यादा परेशान मत होना. मैं जल्द ही वापस लौटूंगा।

राहुल गांधी पर हर तरफ़ से हमले होते ही रहते हैं। उनके खिलाफ़ देशभर में इतने मामले दर्ज हैं कि वे आए दिन किसी न किसी अदालत में पेश होते रहते हैं। मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत की अदालत से दो साल की सज़ा मिलने के बाद 23 मार्च 2023 से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस पर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख़ किया। अदालत ने 4 अगस्त को उन्हें दोषी ठहराए जाने के फ़ैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी।

राहुल गांधी एक नेता हैं, जो पार्टी संगठन को मज़बूत करने के लिए, पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जो उन्हें मिलनी चाहिए या ये कहें कि जिसके वे हक़दार हैं। शायद वे सियासत के लिए बने ही नहीं हैं। उन्हें तो सियासत में धकेला गया है। बहरहाल वे तमाम अफ़वाहों और अपने ख़िलाफ़ रची जाने वाली तमाम साज़िशों से अकेले ही जूझ रहे है और मुस्कराकर उनका सामना कर रहे हैं।

आज का इतिहास

1840 सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का पेटेंट कराया।
1862 रोमानिया के प्रधानमंत्री बार्बू कटारगिउ की हत्या की गई।
1863 पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका का 35वां राज्य बना।
1866 इटली की किंगडम ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की
1874 लुसियन क्लेमन्स को प्रथम यूएस लाइफशविंग मेडल से सम्मानित किया गया।
1877 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कनाडा के ओंटारियो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक टेलीफोन सेवा शुरू की।
1895 कील नहर , जुटलैंडपिनसुला के आधार को पार करते हुए और दुनिया के सबसे व्यस्त कृत्रिम जलमार्ग, को खुलेआम खोला गया था।
1900 बॉक्सर विद्रोह-इंपीरियल चीनी सेना ने बीजिंग में लीजेशन क्वार्टर की 55 दिन की घेराबंदी शुरू की।
1931 कार्ल ब्यूरेश आस्ट्रिया के कुलपति बनाये गए।
1943 बेले आइल, डेट्रायट, मिशिगन में अश्वेतों और गोरों के बीच दंगे शुरू हुए और तीन दिनों तक जारी रहे।
1943 न्यू जॉर्जिया अभियान शुरू हुआ।
1947 कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में एक माफिया हिटमैन ने गैंगस्टर बगसी सिएगल की हत्या कर दी।
1960 माली फेडरेशन (बाद में माली और सेनेगल में विभाजन) को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली।
1960 माली महासंघ ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन सेनेगल और माली में विभाजित होने से दो महीने पहले चली।
1963 व्हाइट मिसाइल और क्रेमलिन के बीच तथाकथित लाल टेलीफोन स्थापित किया गया था, क्यूबाई मिसाइल संकट के बाद कि दोनों देशों के बीच असीमित संचार आवश्यक थे।
1990 ईरान में भूकंप से 40 हजार से अधिक मरे।
1991 एकीकृत जर्मनी की राजधानी फिर से बर्लिन को बनाने के प्रस्ताव को संसद ने मंजूरी दी।
2001 जनरल परवेज मुशर्रफ़ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने।
2003 विकिमीडिया फाउंडेशन एक अमेरिकी गैर-लाभकारी और धर्मार्थ संगठन है जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया में है, जो कई टिकियों का संचालन करता है। यह फाउंडेशन ज्यादातर विकिपीडिया की मेजबानी करने के लिए जाना जाता है।
2005 रूस मालवाहक यान एम-53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचा।
2009 ईरानी चुनाव विरोध के दौरान, नेदा आगा-सोलटन की मौत को वीडियो पर कैप्चर किया गया और इंटरनेट पर व्यापक रूप से वितरित किया गया, जिससे यह मानव इतिहास में संभवत: सबसे व्यापक रूप से देखी जाने वाली मौत बन गई।
2012 लीबिया में सामुदायिक हिंसा में 105 लोगों की मौत, 500 घायल।

भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते सामरिक संबंध

अजय शुक्ला

चार देशों के सुरक्षा गठजोड़ और उसकी सैन्य कवायद- मलाबार युद्धाभ्यास को हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने में सीमित कामयाबी मिली है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने सितंबर 2021 में अपने दो सबसे मजबूत और सक्षम क्षेत्रीय सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को साथ लेकर एक 'ऑकस' समूह बनाया। ऑकस ने तत्काल घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया को पारंपरिक सशस्त्र परमाणु हथियार संपन्न पनडुब्बी बेड़ा तैयार करने में मदद की जाएगी। ऑकस के दो स्तंभ होने थे: स्तंभ एक में ऑस्ट्रेलिया को बगैर परमाणु हथियारों के परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन (प्रपल्शन) का असाधारण हस्तांतरण होना था।

जबकि दूसरे स्तंभ में आठ सैन्य एवं उच्च तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना था जो थे- आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नॉलजी, नवाचार, सूचना साझेदारी, साइबर सूचना, समुद्र के भीतर की गतिविधि, हाइपरसोनिक और काउंटर हाइपरसोनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। हाल ही में निकट सहयोग से जुड़ी एक अन्य घोषणा करते हुए ऑकस ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक उसके तीन सदस्य देश एक नई 'त्रिपक्षीय व्यवस्था' बनाएंगे जो उन्हें पी-8 पोसाइडन सोनोबॉय (यह उपकरण जो पानी में गतिविधियों का पता लगाता है) से सूचना साझेदारी का अवसर देगी। यह ऑकस पिलर2 की पहली तकनीक है जो सामने आ रही है।

ऑकस के सभी तीन सदस्य देश चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए बोइंग निर्मित पी-8 पोसाइडन समुद्री निगरानी विमानों का प्रयोग करते हें जिन्हें दुनिया में पनडुब्बियों का पता लगाने में सबसे सक्षम विमान माना जाता है। पी-8 के काम करने के तरीके की बात करें तो वह सोनोबॉय को पानी में गिराकर पनडुब्बियों का पता लगाता है। सोनोबॉय ट्रैकिंग के आंकड़ों को साझा करना दिखाता है कि ये देश किस तरह सूचनाएं जुटा रहे हैं। आधुनिक युद्ध कला में सॉफ्टवेयर की प्रमुखता को देखते हुए यह बात ध्यान देने लायक है कि ऑकस पहले ही पिलर 2 के माध्यम से सॉफ्टवेयर क्षमता प्रदान कर रहा है। अमेरिका के पास 120 पी-8 पोसाइडन हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास 12 और यूके के पास नौ।

सोनोबॉय सूचना बहुत संवेदनशील होती है। यहां तक कि फाइव आई साझेदारों यानी ऑकस देशों तथा कनाडा और न्यूजीलैंड के लिहाज से भी। तीनों ऑकस देशों के पास उपलब्ध आंकड़े उनकी पहुंच तथा दायरा बढ़ाएंगे क्योंकि वे एक दूसरे के आंकड़े साझा कर सकेंगे। सितंबर 2021 में की गई घोषणा में भारतीय नौसेना की चूक स्पष्ट रूप से देखी गई जो 12 पी-8 विमान संचालित करती है। परंतु ऑकस एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बहुत करीबी साझेदारों के बीच रहना है। अमेरिका ने कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां देने का निर्णय लिया। इससे दशकों पहले एक बार उसने ब्रिटेन को कुछ परमाणु तकनीक संबंधी सहायता प्रदान की थी। कोई

अन्य देश, खासकर भारत को कभी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी की सहायता पेशकश अमेरिका ने नहीं की।

अमेरिका द्वारा अपनी इस सामरिक परंपरा को तोड़ना बताता है कि वह ताइवान को लेकर किसी और संकट की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया की मदद को अनिवार्य मानता है। परंतु अमेरिकी सेना भारत को इन व्यवस्थाओं में शायद ही कभी अपरिहार्य माने अमेरिका मानता है कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन अमेरिकी सेना के साथ लड़ेंगे। यही वजह है कि उसकी नजर में ऑस्ट्रेलियाई सेना को उच्च तकनीक और उपकरणों से लैस करना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया स्वयं को एशिया में अमेरिका का सबसे विश्वसनीय सहयोगी मानता है। पहले विश्व युद्ध से ही वह हर युद्ध में अमेरिका के साथ लड़ा है। अमेरिका के साथ उसके रिश्ते उसकी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए अहम हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए सवाल यह है कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा समर्थन करता है तो हम उसे कितना अधिक क्षमता संपन्न बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही बताता है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलियाई सेना को मजबूत बनाने का निर्णय क्यों लिया।

पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के अन्य संभावित साझेदारों की बात अलग है। जापान का दावा है कि वह पिलर 2 के कई क्षेत्रों में अपने दम पर अहम प्रौद्योगिकी क्षमता रखता है। इसके चलते उसे किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। जापान के समक्ष सीधा सवाल चीन का है। क्या उसे चीन के विरुद्ध अमेरिकी अभियान में शामिल होना होगा? पिलर 2 के मसले पर जापानियों का कहना है कि उन्हें आमंत्रित तो किया गया है लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल होगा या कुछ गंवाना होगा? इस बीच अमेरिका और भारत की नौसेनाएं चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने में सहयोग कर रही हैं। सवाल यह है कि यह सहयोग कितना मजबूत है? भारत के अपने पूर्वग्रह हैं। हमारे कूटनयिकों के मुताबिक भारत के पूर्वग्रह समझे जा सकते हैं क्योंकि अगर आप चीन के पड़ोसी देश हैं तो आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ न करें जिससे वह भड़के। चीन कई तरह से मुश्किल खड़ी कर सकता है।

समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना के पास सहयोग के कई विकल्प हैं क्योंकि नौसेनाएं अक्सर जमीनी सीमा से दूर काम करती हैं जहां जल्दी ध्यान नहीं जाता। इतना ही नहीं समुद्र में दो नौसेनाओं के बीच का सहयोग साफ नजर आने के बजाय छिपा अधिक होता है। अमेरिका और भारत का नौसेना सहयोग अभी संयुक्त अभ्यास के स्तर पर नहीं पहुंचा है हालांकि अमेरिका नॉर्वे और आइसलैंड समेत तमाम देशों के साथ ऐसे अभ्यास करता है। इसकी एक वजह है दोनों के बीच क्षमताओं का बड़ा अंतर। दूसरी वजह है भारत का सुर्खियों से बचने का प्रयास। भारत खामोशी से अभ्यास करना चाहता है हालांकि एक सीमा से परे ऐसा करना मुश्किल होता है।

भारत के लिए क्या सबक हैं? भारत हाशिये पर खड़ा होकर यह देखेगा कि एक परमाणु संपन्न पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही है। परंतु अमेरिका कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि भारत के साथ परमाणु पनडुब्बी के मामले में सहयोग करने में भूराजनीतिक स्थितियां बाधा बन रही हैं। भू-सामरिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से शायद अमेरिका के लिए यही बेहतर है कि वह हाशिये पर रहे और फ्रांस को यह काम करने के लिए प्रोत्साहित करे।

भारत और फ्रांस के बीच पनडुब्बियों और विमानों को लेकर होने वाले सहयोग को देखते हुए यही मानना उचित होगा कि फ्रांस आगे आए और भारत के साथ पनडुब्बी के क्षेत्र में काम करे। फ्रांस की परमाणु पनडुब्बियों को तकनीकी दृष्टि से बेहतरीन माना जाता है। वे हमारी पनडुब्बियों की तुलना में ये छोटी होती हैं और परिचालन के नजरिये से भी ये बेहतर होती हैं। फ्रांस की समुद्री परमाणु तकनीक को अमेरिका से उन्नत माना जाता है। अमेरिकी रिएक्टरों के उलट फ्रांस के परमाणु पनडुब्बी रिएक्टर कम समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते सामरिक रिश्ते के बीच समुद्री रिश्ते को रक्षा, अंतरिक्ष, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों के सरेखित करना बेहतर होगा। दोनों देशों के बीच ये रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं।

मतदाता नहीं चाहते कि चुनाव में दलबदलू नेता जीतें!

राजकुमार सिंह

सत्तापक्ष और विपक्ष की जीत-हार से इतर मतदाताओं ने ज्यादातर दलबदलुओं को नकार कर बड़ा संदेश दिया है। सत्ता को ही राजनीति का पहला और अंतिम सच मानने वाले नेता चुनाव जीतने के लिए दलबदल में संकोच नहीं करते। दलों को भी दलबदलुओं पर दांव लगाने से परहेज नहीं, पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मतदाताओं का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने ज्यादातर दलबदलुओं को नकार दिया। दलबदल की बीमारी किस तरह नासूर बनती जा रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अठारहवीं लोकसभा के चुनाव में डेढ़ सौ से भी ज्यादा

दलबदलुओं पर दलों ने दांव लगाया। भाजपा ने सौ से भी ज्यादा दलबदलुओं को टिकट दिया। उत्तर प्रदेश में यह खेल बड़े पैमाने पर खेला गया। बसपा ने 11 दलबदलुओं को टिकट दिया। जीतना तो बहुत दूर, सभी तीसरे स्थान पर रहे। पिछली बार 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बसपा का इस बार खाता तक नहीं खुला। वैसे सपा द्वारा चुनाव मैदान में उतारे गए नौ में से सात और भाजपा द्वारा टिकट दिए गए तीन में से दो दलबदलू जीत भी गए। दिल्ली के तीन ओर बसे हरियाणा में भाजपा ने दलबदलू अशोक तंवर पर दांव लगाया, पर सिरसा के मतदाताओं ने उन्हें नकारते हुए कांग्रेस की कुमारी शैलजा को चुना। पंजाब में कैप्टन अमरेंद्र सिंह तो कांग्रेस द्वारा 2021 में अपमानजनक तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के कुछ अरसा बाद ही भाजपा में चले गए थे। उनकी सांसद पत्नी परनीत कौर लोकसभा चुनावों से कुछ ही पहले गईं। भाजपा ने टिकट भी दे दिया, पर पटियाला के मतदाताओं ने कांग्रेस की केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकीं परनीत कौर को तीसरे स्थान पर रखा। लुधियाना से भी भाजपा ने तीन बार के कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर दांव लगाया, पर मतदाताओं ने नकार दिया और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग सांसद बन गए। झारखंड में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के चलते मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बावजूद जब सरकार नहीं गिरी, तब भाजपा ने उनकी भाभी सीता सोरेन से दलबदल करवाया। सीता सोरेन को दुमका से लोकसभा टिकट भी दिया, पर मतदाताओं ने नकार दिया। प. बंगाल में तृणमूल से भाजपा में शामिल हुए पांच बड़े दलबदलुओं में से मात्र एक शुभेंदु अधिकारी जीत पाए। यह सूची बहुत लंबी बन सकती है, पर सबक यही है कि दलबदलुओं को सबक सिखाने का संकल्प खुद मतदाताओं को लेना होगा। सुखद संकेत यह है कि दलबदलुओं की चुनावी सफलता की दर लगातार गिर रही है। एक अध्ययन के मुताबिक यह दर 2014 और 2019 में क्रमश- 66.7 और 56.5 थी, जो 2024 में 32.7 रह गई यानी मतदाताओं ने दो-तिहाई दलबदलुओं को नकार दिया।

रूस-यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने का रास्ता कैसे निकलेगा?

नीरज कुमार दुबे

यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने का रास्ता तलाशने के लिए स्विट्जरलैंड में आयोजित दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में 90 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में हालांकि कोई ठोस हल नहीं निकल सका और आगे भी शांति के प्रयास जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गयी। इस सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था इसलिए इसके सफल होने की संभावना पहले से ही कम थी। रूस ने भी इस सम्मेलन को समय की बर्बादी बताया था। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के समक्ष एक सशर्त शांति प्रस्ताव रखा था जिस पर भी इस सम्मेलन में चर्चा की गयी और उसे लगभग खारिज कर दिया गया। इस सम्मेलन से चीन भी नदारद रहा।

हम आपको यह भी बता दें कि भारत समेत कुछ देशों ने यूक्रेन में शांति के लिए स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए और किसी भी विज्ञप्ति या दस्तावेज से खुद को अलग कर लिया। भारत के अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात ने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। गौरतलब है कि भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स आर्थिक समूह के सदस्य हैं और इन सभी का रूस के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध है।

शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले स्विट्जरलैंड ने कहा है कि 90 से अधिक देशों ने वार्ता में भाग लिया और उनमें से अधिकांश ने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा ब्राज़ील, जिसने पर्यवेक्षक देश के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लिया, उसने भी हस्ताक्षर नहीं किये। तुर्की के बारे में माना जा रहा था कि वह भी हस्ताक्षर नहीं करेगा लेकिन चूंकि वह रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है इसलिए उसने दस्तखत कर दिये।

बताया जा रहा है कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 90 देशों में से लगभग 83 ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। बयान में दोहराया गया कि युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। संयुक्त बयान में आह्वान किया

गया है कि युद्ध के सभी कैदियों को रिहा किया जाये और निर्वासित तथा अवैध रूप से विस्थापित किए गए सभी यूक्रेनी बच्चों को यूक्रेन वापस भेजा जाये। शिखर सम्मेलन में कार्य समूहों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक में शामिल देशों ने यूक्रेन से ज़ापोरीज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर पूर्ण संप्रभु नियंत्रण रखने का भी आह्वान किया। इस बैठक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने सहमति जताई है कि वह शांति कायम करने के लिए विभिन्न समूहों में रहते हुए काम करते रहेंगे और एक बार शांति के लिए कार्य योजना तैयार हो जाने पर, दूसरे शिखर सम्मेलन के आयोजन का रास्ता खुला रहेगा। जेलेंस्की ने चीन से भी अपील की है कि वह रूस को शांति के लिए मनाने में मदद करे।

जहां तक इस बैठक के दौरान अमेरिका के रुख की बात है तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रस्तुत शांति प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया। सुलिवन ने शांति शिखर सम्मेलन में कहा, अगर रूस का प्रस्ताव माना जाता है तो यूक्रेन को न केवल वह क्षेत्र छोड़ना होगा जिस पर रूस ने वर्तमान में कब्जा कर रखा है, बल्कि यूक्रेन को अतिरिक्त क्षेत्र भी छोड़ना पड़ सकता है। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी उपस्थित थीं। उन्होंने इस अवसर का उपयोग यूक्रेन के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा करने के लिए किया। यह पैसा यूक्रेन में मानवीय कार्यों में मदद और वहां युद्ध से जर्जर बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में उपयोग होगा। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका देश यूक्रेन की मदद के लिए आने वाले महीनों में यहां मौजूद देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी करने की योजना बना रहा है।

दूसरी ओर, भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच ''ईमानदारी और व्यावहारिक भागीदारी'' का आह्वान किया। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) पवन कपूर ने स्विस रिसॉर्ट बर्गेनस्टॉक में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्षों सहित 90 से अधिक देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अपने संक्षिप्त संबोधन में भारत के वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि शांति शिखर सम्मेलन में भारत भागीदारी और यूक्रेन के शांति फार्मूले पर आधारित वरिष्ठ अधिकारियों की कई पूर्व बैठकें ''हमारे स्पष्ट और सुसंगत दृष्टिकोण के अनुरूप हैं कि स्थायी शांति केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।'' भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन और समापन पूर्ण सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''भारत ने इस शिखर सम्मेलन से जारी होने वाले किसी भी विज्ञप्ति या दस्तावेज से खुद को संबद्ध नहीं किया है।'' मंत्रालय ने बयान में कहा, ''सम्मेलन में भारत की भागीदारी, साथ ही यूक्रेन के शांति फार्मूले पर आधारित पूर्ववर्ती एनएसए या राजनीतिक निदेशक स्तर की बैठकों में भागीदारी, संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को सुगम बनाने के हमारे सतत दृष्टिकोण के अनुरूप है।'' विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का मानना है कि इस तरह के समाधान के लिए संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों के बीच ईमानदारी और व्यावहारिक भागीदारी की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा, ''इस संबंध में, भारत सभी हितधारकों के साथ-साथ दोनों पक्षों के साथ बातचीत जारी रखेगा, ताकि शीघ्र और स्थायी शांति लाने के लिए सभी गंभीर प्रयासों में योगदान दिया जा सके।'' दूसरी ओर, स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि 83 देशों और संगठनों ने ''यूक्रेन में शांति पर उच्च स्तरीय सम्मेलन'' के अंत में संयुक्त बयान को मंजूरी दी।

अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रहे हैं पाक प्रधानमंत्री

मरिआना बाबर

बोलने की आजादी, जुझारू व हर तरह के सेंसरशिप से आजाद मीडिया, असहमति को सहन करने की ताकत, असंतोष को दबाना-ये सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम दुनिया भर में पढ़-सुन रहे हैं। हर जगह शासक और ताकतवर लोग मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं खबरों को प्रकाशित एवं प्रसारित करने की अनुमति देते हैं, जो उन्हें पसंद हों। दक्षिण एशिया के देश दुनिया के अन्य देशों से अलग नहीं हैं और इस हफ्ते मैं अमर उजाला के पाठकों का ध्यान इस खबर की ओर दिलाना चाहूंगी कि पाकिस्तान की मुख्य पार्टियां यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हो गई हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, ताकि मीडिया की आवाज को और दबाया जा सके।

हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को चुप कराने संबंधी खबरों में सबसे निराशाजनक खबर दिवंगत बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आई है, जिसने पंजाब प्रांत की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की मरियम नवाज सरकार के नए विवादास्पद पंजाब मानहानि विधेयक, 2024 को पारित कराने में साथ दिया है, ताकि उन आक्रोशित नागरिकों को शांत किया जा सके, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अतीत में जनरल जिया उल हक जैसे सैन्य तानाशाहों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी और विरोध करने वालों को सार्वजनिक रूप से कोड़े तक मारे थे। आज भी मेरे एक बुजुर्ग सहकर्मी नासिर जैदी जीवित हैं, जो बताते हैं कि कैसे तानाशाह ने उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने की हिम्मत करने के लिए कोड़ों से पीटा था। आज असैन्य तानाशाही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। यही नहीं, अब पत्रकारों के गायब होने और उनकी हत्या का खतरनाक चलन भी दिख रहा है।

इससे पहले दुनिया भर के तानाशाहों की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ महीने पहले पूरे पाकिस्तान में एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब लोगों को वीपीएन इंस्टाल करना पड़ता था, जो सिस्टम को अनब्लॉक करने में मदद करता है, ताकि उपयोगकर्ता

ट्वीट कर सकें। इनमें से कुछ वीपीएन मुफ्त हैं, जबकि कुछ अन्य के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, तभी एक्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जहां आम लोगों को एक्स का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री खुद और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सुबह-शाम एक्स का उपयोग कर अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं। इस हफ्ते हम सबको इस बात पर हंसी आई कि एक्स को ब्लॉक किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री को आम चुनाव में जीत की बधाई ट्वीट करके दी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके जवाब दिया। इस पाखंड को सबने समझ लिया कि पाकिस्तान के राजनेता कैसे अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब पंजाब प्रांत की सरकार ने पंजाब मानहानि विधेयक, 2024 के लिए आधिकारिक रूप से गजट अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे विवादास्पद कहा जाता है। नए कानून का उद्देश्य यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं से निपटना है, जिससे 'फर्जी खबर' फैलाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सके। इस बात से हर कोई सहमत है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट किया जाता है, उनमें से कुछ नफरत से भरा और अस्वीकार्य होता है। लेकिन उन अकाउंट को बंद करने के बजाय, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप पूरे नेटवर्क को बंद नहीं कर सकते। पत्रकार समुदाय ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया है। गैर-लोकतांत्रिक बताते हुए इसकी निंदा की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से भी प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के कारण कड़ी आपत्ति जताई गई है। अंग्रेजी दैनिक द डॉन ने संपादकीय में लिखा है- %ये घटनाक्रम इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसे आम नागरिक अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सके हैं। यहां चिंता यह नहीं है कि नागरिकों को जो कुछ भी वे कहना या उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें उसकी अनुमति दी जानी चाहिए, आखिरकार नागरिक होने के नाते वे भी देश के कानून से बंधे हैं। बल्कि डर यह है कि इन हथकंडों का इस्तेमाल पुलिस और सत्ता से असहमत केवल चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा।%

इस हफ्ते की दूसरी चौंकाने वाली खबर यह है कि शहबाज शरीफ सरकार अब इंटरनेट फायरवॉल बना रही है, जिसे कथित तौर पर अधिकारियों ने गुप्त रूप से लागू करना शुरू कर दिया है, जो उन्हें पाकिस्तानी उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट पर पोस्ट की जाने वाली या देखी जाने वाली हर चीज पर जासूसी करने की अनुमति देगा। यह इंटरनेट फायरवॉल ग्रेट फायरवॉल की तरह है, जिसका उपयोग चीनी अधिकारी अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए करते हैं।

यह इंटरनेट फायरवॉल इंटरनेट पुलिस की तरह काम करेगा। खबरें बताती हैं कि सरकार ने विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे यह निगरानी की जा सकेगी कि कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट पर क्या कह, सुन या पढ़ रहा है। एक दृष्टिकोण है कि इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इस परियोजना के पूरा होने से पहले उचित मंचों पर इसे जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान तानाशाहों को अपने लोगों पर नियंत्रण बढ़ाने का जोखिम नहीं ले सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के निरंतर प्रयासों पर पूर्व संपादक अब्बास नासिर ने कहा, यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों मीडिया पर होने वाली किसी भी चर्चा में लगभग हमेशा पारंपरिक मीडिया को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन समाचार साइटों के अलावा, चौबीसों घंटे चलने वाले दर्जनों टीवी चैनल और समाचार पत्र।

भाजपा क्यों पिछड़ी? आखिर क्यों चेता रहा है आरएसएस?

प्रवीण बागी

लोकसभा चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है। मतदाताओं ने इस बार उसे सिर्फ हड़काकर छोड़ दिया है। अगर इस पर भी वह नहीं चेतती है और पार्टी तथा सरकार की कार्यशैली में बदलाव नहीं आता है तो अगली बार उसे विपक्ष में बैठने को तैयार रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी सार्वजनिक रूप से मोदी सरकार के कामकाज और व्यवहार से अप्रसन्नता व्यक्त कर उसे सुधरने की नसीहत दी है। हर काम का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खुद लेने को भी उन्होंने अच्छा नहीं माना है। मणिपुर में एक साल से जारी हिंसा पर केंद्र की उदासीनता पर भी संघ प्रमुख ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। बेशक मोदी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक काम किए जो आजादी के तुरंत बाद होने चाहिए थे। देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है। विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिया है। आतंकी कार्रवाईयां और नक्सली हिंसा पर करीब करीब काबू पा लिया गया है। डिजविंग व्यक्तियों के चयन से पद्म सम्मान का %सम्मान% बढ़ा है। हर घर शौचालय और स्वच्छता के प्रति जागरूकता की दिशा में सराहनीय कार्य हुए हैं। और भी कई अच्छे काम हुए हैं। इसके बाद भी जनता ने इस सरकार को अपेक्षित समर्थन क्यों नहीं दिया, इस पर गहन चिंतन की जरुरत है। खुद प्रधानमंत्री मोदी की काशी से एक लाख 52 हज़ार वोटों से जीत यह दर्शाती है कि वहां के वोटर भी उनसे खुश नहीं हैं। काशी के लिए इतना काम करने के बाद भी मोदी के वोट क्यों घटे? इस पर खुद मोदी जी को विचार करना चाहिए। अयोध्या की हार भाजपा के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। कहां चूक हुई? वहां के मतदाता क्यों मुंह फेर लिए? जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे का नारा क्यों हवा में उड़ गया ? मेरा बूथ सबसे मजबूत और पन्ना प्रमुख की परिकल्पना क्यों नाकाम रही? पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा काम और मजबूत नेता की छवि के बाद भी यूपी में भाजपा के औंधे मुंह गिरने के पीछे क्या पार्टी के अंदर की गुटबाजी जिम्मेवार है? पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है लेकिन यह चर्चा आम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद को छोटा करने के लिए साजिश के तहत कमजोर और बदनाम उम्मीदवार दिए गए? अगर ऐसा हुआ है तो फिर भाजपा का पतन तय है। यह भी लांक्षन लग रहा है कि भाजपा का कांग्रेसी करण होता जा रहा है। भाजपा का केंद्रीकरण और उसके नेताओं की आत्ममुग्धता उसके लिए घातक हुई। मोदी ने अपने मंत्रियों को उभरने नहीं दिया। हर जगह वे ही वे नजर आए। मंत्रियों की हैसियत सहयोगियों की नहीं सहायक की कर दी गई थी। इस ओर संघ प्रमुख ने भी इशारा किया है। हालांकि यह भी सही है कि हमारा देश व्यक्ति पूजक है, समाज पूजक नहीं। इस वजह से मोदी का एकछत्र नेता के रूप में खुद को स्थापित करना भाजपा के लिए लाभदायक भी रहा। व्यक्ति पूजा के कारण ही नेहरू वंश इतने वर्षों तक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखने में सफल रहा। मोदी ने उसी के अस्त्र से उसे धराशाई किया। लेकिन वह अस्त्र भोथरा हो रहा है। अपने भाषणों में अन्य नेताओं की तरह कई बार मोदी ने भी मर्यादाएं लांघी, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। यह याद रखना होगा की अपने ऊटपटांग भाषणों के चलते ही राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा से विभूषित किया गया था और उनके भाषणों के मीम बनते रहे हैं। प्रधानमंत्री समेत भाजपा के अनेक नेता भी कई बार वही गलती करते दिखे। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होना और अग्निवीर योजना से युवा वर्ग मोदी सरकार से उदासीन नजर आता है। वोटिंग के दिन वह घर बैठा रहा। वोट देने नहीं निकला। वेतनभोगी मध्यम वर्ग की तरफ भाजपा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसे यह वर्ग भी मुंह फुलाए हुए है। इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। भाजपा विपक्ष के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के प्रचार का प्रभावी काट नहीं कर पाई। इससे भी उसे क्षति उठानी पड़ी।

हर इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयासरत रहता है। उसके लिए जरूरी होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी अपनी आत्मा पर विश्वास या अपने आप पर विश्वास।

जीवन में हर काम अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर ही होते हैं। आत्मविश्वास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरूरी होता है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है।

अगर होता भी है तो निम्नस्तर का या आधा-अधूरा व ख़राब। आइए, हम जानते हैं आत्मविश्वास के बारे में-

यह है आत्मविश्वास बढ़ाने की कुंजी

क्या है आत्मविश्वास?

आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। इससे महान कार्यों के संपादन में सहजता और सफलता हमें प्राप्त होती है। बगैर आत्मविश्वास के इन कार्यों की सफलता संदिग्ध ही बनी रहती है।

एकाग्रचित बनें

जिस भी व्यक्ति का मन शंका, चिंता और भय से भरा हो वह बड़े कार्य तो क्या, साधारण से साधारण कार्य भी नहीं कर सकता है। चिंता व शंका आपके मन को कभी भी एकाग्र न होने देंगे अतः आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु अपने मन से सभी प्रकार के संदेह निकालें तथा एकाग्रता को बढ़ाएं।

आत्मविश्वास अद्भुत शक्ति

आत्मविश्वास एक अद्भुत शक्ति होती है। इसके बल से व्यक्ति तमाम विपत्तियों तथा शत्रुओं का सामना कर लेता है। संसार के अभी तक के बड़े से बड़े कार्य आत्मविश्वास के बलबूते ही हुए हैं और हो रहे हैं तथा होते रहेंगे।

बच्चों में आत्मविश्वास भरें

माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों में आत्मविश्वास भरें। उनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी इस प्रकार के नकारात्मक शब्द कि तुम कुछ नहीं जानते या तुम में इस बात की कमी है कभी नहीं कहने चाहिए। इससे बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है तथा इससे उनमें हीनभावना जागृत होती है तथा वे कुंठित हो जाते हैं। आज जग में जो निराशा की भावना तथा गरीबी दिखाई दे रही है उसके पीछे प्रमुख कारण यही हीनभावना है।

आत्मविश्वास से भरपूर होने का अभ्यास करें :

आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह प्रयास करें कि मैं सक्षम हूं। मैं यह कार्य कर सकता हूं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। महानायक अमिताभ बच्चन को भी पहली बार अभिनय करते वक्त काफी डर लगता था। जब अधिक डर लगता था तो वे स्वयं से कहते थे कि मैं जिसका रोल कर रहा हूं वह व्यक्ति मैं ही हूं ऐसा सोचते व करते उनका आत्मविश्वास बढ़ गया व आज वे कहलाते हैं।

ऐसे बढ़ाएं आत्मविश्वास :

सकारात्मक चिंतन हो : सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा सकारात्मक चिंतन करे। सकारात्मक विचारधारा के लोगों के साथ ही रहें। कहा भी जाता है कि जैसी संगति, वैसी उन्नति। जैसी आपकी विचारधारा होगी, दिमाग भी वही सोचने लगता है अतः सकारात्मक ही सोचें तथा साथ ही अपनी खामियों को भी स्वीकार करें।

व्यक्तित्व को निखारिए

अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देते रहें तथा हमेशा अपना व्यक्तित्व आकर्षक बनाए रखिए। बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें। संकीर्ण मनोवृत्ति का न बनें। स्वयं को नई सूचनाओं से अपडेट रखें तथा आसपास के परिवेश से भी तालमेल बैठाए रखें। इस प्रकार की चंद बातों को आजमाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं तथा जीवन में नित नई उन्नति कर सकते हैं। तो आप भी आज से जुट जाइए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने व तरक्की करने में।

बीती ताहि बिसारि दे

अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों, असफलताओं को आप भुलाकर नई शुरुआत करें। भविष्य की योजना बनाएं तथा लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति में जुट जाएं।

उपलब्धियां याद रखें

आत्मविश्वास की कुंजी है असफलता को स्वीकारना। श्रेष्ठ काम के लिए स्वयं को सराहें। आपके द्वारा सफलतापूर्वक किया गया काम आप फिर दोहरा सकते हैं इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

नया सीखते रहें

यदि आपको वर्तमान परिस्थिति जटिल लगे तो उसे नए तरीके से सीखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नया सीखने से आपका आत्मविश्वास तथा उत्साह बढ़ेगा तथा आपको इस बात का एहसास होता रहेगा कि मैं कुछ अलग व नया जानता हूं। इससे आपका काम कम समय में बेहतर तरीके से होगा।

● रवीन्द्र गुप्ता

म्यूजिक में रखते हैं दिलचस्पी तो इस फील्ड में बनाएं कॅरियर, बिना एक्सपीरियंस के कर सकते हैं तगड़ी कमाई

आज के समय में लोग अलग-अलग क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाते हैं। हालाँकि पहले के समय में लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टर के पेशे को सबसे अच्छा प्रोफेशन मानते थे। लेकिन समय के साथ लोगों का नेरेटिव बदल गया है। बता दें कि अपने टैलेंट और पैशन की बदौलत कोई भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वहीं इससे अच्छी कमाई भी की जा सकती है। क्योंकि आज के दौर लोगों को कुछ नया और हटके करना पसंद कर रहे हैं।

वर्तमान समय में अगर आपके अंदर कोई स्किल या टैलेंट है, तो आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आजकल लोग म्यूजिक के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। हर वर्ग के लोगों को म्यूजिक में गहरी रुचि होती है। यदि आपके अंदर भी सिंगिंग टैलेंट है, तो आप इसके जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। हालांकि म्यूजिक इतना अधिक आसान नहीं होता है। इस फील्ड में सिर्फ वही अपना कॅरियर बना सकते हैं, जिनके अंदर क्रिएटिविटी हो और म्यूजिक के प्रति जुनून हो।

कई सारे लोगों के अंदर टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन इसके बाद भी वह पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अपने टैलेंट को किस तरह से निखारा जाए, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से बिना एक्सपीरियंस के आप म्यूजिक में अपना कॅरियर बना सकते हैं।

कैसे बनाएं कॅरियर

म्यूजिक इंडस्ट्री में ऑनलाइन और सोशल मीडिया की वजह से काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और उनको काफी पसंद भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट और पैशन के जरिए लोग अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। पहले के समय में यह सुविधा नहीं होने के कारण बहुत कम लोग म्यूजिक को बतौर पैशन चुन पाते थे।

ऐसे में अगर आप भी म्यूजिक में इंट्रेस्ट रखते हैं और आपके अंदर कुछ अलग करने का हुनर है। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। यदि आपकी क्रिएटिविटी लोगों को पसंद आती है, तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और समय के साथ आप फेमस भी हो सकते हैं। जिससे आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी।

हालांकि इसके लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती हैं। आप चाहें तो वीडियो शूट करने के लिए अपने कमरे को शूटिंग रूम बना सकते हैं। वहीं अगर बाहर निकलकर शूटिंग करना संभव है, तो आप किसी अच्छे स्पॉट पर भी शूट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी वीडियो होगी, उतना ही लोगों का प्यार आपको मिलेगा।

यूट्यूब से करें कमाई

अगर आपके पास म्यूजिक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर इसको लेकर पैशन है। तो आप दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखाने के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर आप शॉर्ट वीडियोज बनाकर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन शुरूआत के समय में आपको थोड़ा का धैर्य बनाकर रखना होगा। सही समय पर ट्रेंड को फॉलो करते हुए वीडियो डालेंगे तो आपके पोस्ट की रीच बढ़ सकती है। यूट्यूब से आप न सिर्फ अच्छे कलाकार बल्कि आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आप बतौर म्यूजिशियन अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं, तो इस फील्ड में स्पेशल कोर्स कर प्लेसमेंट के जरिए आगे का रास्ता चुन सकते हैं।

जब किसी आलसी के साथ काम करना पड़े

आलसी कर्मचारी की वजह से उन पर काम का बोझ बढ़ जाता है और उसकी वजह से वे अक्सर क्रोधित तथा नाराज रहते हैं।

10 में से कम से कम 9 कर्मचारी अपने किसी ऐसे सहकर्मी का नाम अवश्य ले सकते हैं जो उनकी नजर में बेहद आलसी हो और अपना काम करने से भी बचने की कोशिश करता रहता हो। चार में से एक कर्मचारी यह भी मानता है कि ऐसे आलसी कर्मचारी की वजह से उन पर काम का बोझ बढ़ जाता है और उसकी वजह से वे अक्सर क्रोधित तथा नाराज रहते हैं।

अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि दफ्तरों में बेहतर काम करने वालों और मेहनती कर्मचारियों पर ही काम का अधिक बोझ डाला जाता है जबकि आलसी लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है परंतु ऐसे कर्मचारियों के साथ सहजता के साथ कार्य करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पेश हैं इसी संबंध में कुछ टिप्स–

आरोप-प्रत्यारोप से बचें

- आलसी सहकर्मी से किसी जिज्ञासु मित्र की तरह बातचीत करने की कोशिश करें, न कि क्रोधित सहकर्मी के रूप में।
- उस सहकर्मी को बताएं कि आप दोनों के लक्ष्य सांझे हैं। उसे समझाएं कि आप उसे लेकर क्यों चिंतित हैं?
- स्पष्ट बात करें। उससे तथ्यों को सांझा करें। उसे बताएं कि कम्पनी की उससे अपेक्षाएं क्या हैं जबकि वह कैसा प्रदर्शन कर रहा है और उनमें कितना अंतर है।
- उससे पूछें कि क्या इस स्थिति को वह किसी और ढंग से देखता रहा है।
- अच्छे कर्मचारी जोकि गुणवत्ता तथा उत्पादकता को लेकर वास्तव में चिंतित होते हैं, कई बार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का फैसला करते हैं लेकिन स्थिति को बद से बदतर बनाने से बचने के लिए इस मामले में कुशलता होना आवश्यक है। असली लक्ष्य दफ्तर में तनाव को कम करना तथा अपनी टीम के मनोबल को उठाना या कम्पनी को लाभ पहुंचाना होता है।
- यदि आप अपने किसी सहकर्मचारी के आलसीपन या कामचोरी को देखकर चुप नहीं रह सकते हैं और आपके हस्तक्षेप से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है तो आपको फैसला लेना होगा कि आप कर्मचारियों की कार्यक्षमता में असमान्यता के तथ्य को स्वीकार करके काम करते रहें या काम से अपने हाथ पीछे खींच लें।

नौकरी की तलाश में दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं

बेशक कुछ आवेदनकर्ताओं को किसी नौकरी में रुचि न रही हो या फिर उन्हें वह नौकरी अपने मतलब की न लगी हो या फिर तनख्वाह से वे संतुष्ट न हों परंतु इंटरव्यू पर न पहुंचने या नौकरी ज्वाइन नहीं करने की सूचना कम्पनी को जरूर देनी चाहिए।

पेश हैं कुछ नियम जिनका पालन नौकरी के लिए आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को करना चाहिए। अक्सर नौकरी तलाश करने वाले आवेदकों की शिकायत होती है कि इंटरव्यू के बाद उन्हें नियोक्ताओं की तरफ से कोई खबर नहीं मिलती है परंतु कुछ शिकायतें नियोक्ताओं की आवेदकों से भी होती हैं।

उनकी अक्सर शिकायत होती है कि आवेदन करने वाले कई सारे लोग साक्षात्कार के लिए पहुंचते ही नहीं जिसकी वे पहले कोई खबर भी नहीं देते हैं। ऐसे भी कई आवेदक हैं जिन्हें नौकरी दिए जाने के बाद वे ज्वाइनिंग ही नहीं करते और न ही इस बारे में कोई सूचना देते हैं। बेशक कुछ आवेदनकर्ताओं को किसी नौकरी में रुचि न रही हो या फिर उन्हें वह नौकरी अपने मतलब की न लगी हो या फिर तनख्वाह से वे संतुष्ट न हों परंतु इंटरव्यू पर न पहुंचने या नौकरी ज्वाइन नहीं करने की सूचना कम्पनी को जरूर देनी चाहिए।

उनके द्वारा बगैर बताए गायब हो जाने की बात से उन लोगों के लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं जो भविष्य में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं इसलिए आवेदनकर्ता निम्न बातों का खास तौर पर ध्यान रखें।

- यदि आपको इंटरव्यू के लिए समय दिया गया है तो समय पर पहुंचें। यदि किसी वजह से आप इंटरव्यू पर नहीं पहुंच सकते हैं तो समय पूर्व फोन करके इसकी सूचना कम्पनी को दें।
- यदि आपको नौकरी पर रख लिया गया है तो काम पर समय पर पहुंचें या फिर समय रहते पर्याप्त कारण बताते हुए नौकरी न करने की सूचना कम्पनी को देना आवश्यक है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस के के. सुरेश हो सकते हैं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर

नईदिल्ली। कांग्रेस के के. सुरेश लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनने वाले हैं। सत्रों की ओर से ऐसे दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा कि जब तक केंद्र अध्यक्ष पद पर औपचारिक निर्णय नहीं ले लेता, तब तक सुरेश 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करेंगे। 68 वर्षीय सुरेश केरल के मावेलिकारा से सांसद हैं और सबसे लंबे समय तक संसद सदस्य रहने वाले सदस्य हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा, जिसके दौरान निचले सदन के नए सदस्य शपथ लेंगे और अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 जून को संसद बुलाने से पहले राष्ट्रपति भवन में सुरेश को पद की शपथ दिलाएंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रोटेम एक लैटिन मुहावरा है। इसका मतलब है फिलहाल के लिए। इसलिए, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है। पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नए सदन की बैठक से पहले अपना पद खाली कर देते हैं।

प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे के मद्देनजर बुधवार को राज्य से संबंधित कुछ विषयों को लेकर उन पर निशान साधा और सवाल किया कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, एक तिहाई प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए बिहार जा रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान हमने उनसे कुछ सवाल पूछे थे। हम आशा करते हैं कि वह अब इनके उत्तर देंगे। उन्होंने सवाल किया, प्रधानमंत्री के वादे के अनुरूप बिहार को विशेष राज्य का दर्ज़ा क्यों नहीं दिया गया? कांग्रेस महासचिव ने कहा, 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तब उन्होंने कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्ज़ा देने का वादा किया था। केंद्र की अपनी बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट के अनुसार, बिहार भारत का सबसे ग़रीब राज्य है।

किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति भाजपा में शामिल

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में शामिल हो गईं। भाजपा कार्यालय पहुंची श्रुति ने कहा, आज यहां लहर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा की नीतियां राज्य और देश को आगे ले जा रही हैं, लोग बार-बार प्रधानमंत्री चुन रहे हैं - यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि भाजपा की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। हम सभी यहां भाजपा को मजबूत करने के लिए हैं...हम आगे की ओर देख रहे हैं। हरियाणा में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। किरण हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू हैं। उन्हें वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धुरंधर माना जाता है। मां और बेटी दोनों ने मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

नईदिल्ली। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे जल संकट पर हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह शुक्रवार से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगी। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा सरकार से अनुरोध करके और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हर संभव कदम उठाने की कोशिश की है। हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। मंगलवार को दिल्ली से अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सरकार के अधिकारियों से मिला लेकिन उन्होंने पानी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। आतिशी ने बताया कि दिल्ली के लोगों की पीड़ा सारी हदें पार कर चुकी है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। अगर अगले दो दिनों में दिल्ली को उसके वाजिब हिस्से का पानी नहीं मिला तो मैं पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करूंगी।

कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। कोर्ट में दाखिल ईडी ने आरोप पत्र में कहा था कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी। उसने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया, जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी।

आग की लपटें किताबें जला सकती है, लेकिन ज्ञान को नहीं : प्रधानमंत्री मोदी

■ **ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस देश को समर्पित**

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया और इसे भारत की जीवंत संस्कृति और विरासत का प्रतीक कहा। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। कैंपस का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि देश की एक पहचान है। उन्होंने कहा कि नालंदा भारत की शैक्षणिक विरासत और जीवंत सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक है। अपने प्राचीन खंडहरों के निकट नालन्दा का पुनर्जागरण। यह नया परिसर दुनिया को भारत की क्षमता से परिचित कराएगा।

मोदी ने कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही, साथ ही मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। उन्होंने कहा कि नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा उद्घोष है इस सत्य का... कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं... लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकतीं। उन्होंने कहा कि नालंदा बताएगा...जो राष्ट्र, मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं... वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।

पीएम मोदी ने इतिहासकारों के दावों का जिक्र करते हुए कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में लाखों किताबें और पांडुलिपियां अफगान कमांडरों द्वारा जला दी गईं थीं, कहा, नालंदा इस सत्य की घोषणा है। किताबें आग की लपटों में जल सकती हैं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती हैं। अफगान कमांडरों द्वारा जला दिया गया। फ़ारसी इतिहासकार सिराज ए मिनाज ने अपनी तबकात-ए-नसीरी में दावा किया कि अफगान कमांडर बख्तियार खिलजी ने नालंदा में 9 मिलियन से अधिक किताबें जला दी थीं।

उन्होंने कहा कि नालंदा केवल भारत के ही अतीत

का पुनर्जागरण नहीं है। इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि प्राचीन नालंदा में बच्चों का प्रवेश उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रीयता को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से मजबूती देनी है। दुनिया के कई देशों से यहां छात्र आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है।

मोदी ने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएँ मौजूद हैं। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा! लेकिन, किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है, योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मेरा मिशन है...भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में हो।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। इसके बाद ही विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में शुरू किया गया था। इस विश्वविद्यालय का नया कैंपस से बेहद शानदार है लिए इसके बारे में जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी। इस नए कैंपस को पुराने कैंपस के पास में ही बनाया गया है।

इस नालंदा यूनिवर्सिटी ने नए कैंपस में दो अकेडेमिक ब्लॉक का निर्माण किया गया है। यहां कुल 40 क्लासरूम बनाए गए है। इन क्लास रूम में कुल 1900 छात्र बैठ कर पढ़ सकते है। इस यूनिवर्सिटी कैंपस में दो ऑडिटोरियम बनाए गए है, जिनकी क्षमता 300 सीटों की है। यहां इंटरनेशनल सेंटर और एम्फीथिएटर भी है, जिसकी क्षमता 2000 लोगों को बैठाने की है।

छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुविधा भी दी गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस पर्यावरण अनुकूल है। कैंपस में पानी को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट लगाया है। यहां 100 एकड़ की वॉटर बॉडी के साथ कई सुविधाएं पर्यावरण अनुकूल है। विश्वविद्यालय में छह अध्ययन केंद्र हैं जिनमें बौद्ध अध्ययन, दर्शन और तुलनात्मक धर्म स्कूल; ऐतिहासिक अध्ययन स्कूल; पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन स्कूल; और सतत विकास और प्रबंधन स्कूल शामिल हैं।

दिल्ली के सभी मंडलों में भाजपा ने निकाली केजरीवाल सरकार पर धिक्कार पदयात्रा

नई दिल्ली। दिल्ली की भ्रष्ट केजरीवाल सरकार जिसने बूंद-बूंद पानी के लिए दिल्ली वासियों को तरसाया और पिछले दस वर्षों में दिल्ली जलबोर्ड को अपनी कमाई का अड्डा बना लिया। सिर्फ अपने निजी हितों को प्राथमिकता देकर ना ही सिर्फ जल बोर्ड को लूटने का काम किया बल्कि दिल्ली के खजाने को भी खाली करने से पीछे नहीं हटी। ऐसी घोटालेबाज आम आदमी पार्टी की सरकार के विरोध में आज दिल्ली के सभी मंडलों में विभिन्न मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में केजरीवाल सरकार पर धिक्कार पदयात्रा निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया गया।

इंदिरा कैंप, एंड्र्यूजगंज में प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाजपा सांसद बांरी स्वराज, पार्षद शरद कपूर, मंडल अध्यक्ष सचिन अहूजा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं इंदिरा कैंप निवासी सम्मलित हुए।

इसके अलावा भाजपा द्वारा आज जिन प्रमुख स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुआ उनमें शामिल थे किशन गंज के मोती बाग चौक पर भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल द्वारा, रिठाला के मंदिर रोड पर सांसद योगेंद्र चंदोलिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी में और आदेश गुप्ता ने सरोजनी नगर मार्केट में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

लोकसभा अध्यक्ष चुनाव : जो प्रधानमंत्री मोदी को है पसंद, उसके साथ है हम

सहयोगी दलों ने भाजपा को पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन

नईदिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सबसे बड़ी पार्टी है, अपने सहयोगियों से इस पर चर्चा कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न सहयोगियों से स्पीकर पद पर चर्चा के लिए फोन किया है। इसमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में छोटे सहयोगियों के साथ चर्चा भी शामिल है। सूत्रों ने बताया है कि एनडीए गठबंधन के सहयोगियों ने उस उम्मीदवार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है जिसे भाजपा इस पद के लिए नामित करने का फैसला करती है।

एक सूत्र ने बताया कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए सहयोगियों से उनके सुझाव लेने के लिए बुलाया गया है। हालाँकि, अधिकांश सहयोगियों ने किसी विशेष व्यक्ति को कोई प्राथमिकता या पसंद नहीं दी है। भाजपा के शीर्ष

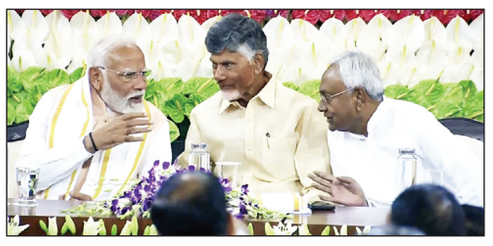

नेतृत्व को यह बता दिया गया है कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक एकजुट इकाई बनी रहेगी और इस पद पर निर्णय लेना उनका निर्णय है जो गठबंधन के सभी सहयोगियों के लिए स्वीकार्य होगा।

भाजपा के शीर्ष नेताओं ने गठबंधन सहयोगियों को यह भी बताया है कि वे गठबंधन सहयोगियों में से किसी एक को उपाध्यक्ष पद देने के इच्छुक होंगे। हालाँकि, विपक्ष भी इस पद के लिए अपना दावा पेश कर सकता है क्योंकि इसके लिए माँग करने के लिए संख्या बल भी उनके पास है। कुछ सहयोगियों, जिनमें वरिष्ठ सांसद भी शामिल हैं, ने भाजपा से अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार लाने का अनुरोध किया है, जिसमें सर्वसम्मति प्राप्त की जा सके।

गठबंधन के सहयोगियों ने सरकार को बताया कि 2014 और 2019 अलग थे जब बीजेपी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था। लेकिन इस बार अधिक उत्साही और आक्रामक विपक्ष होगा जिसे अच्छी संख्या का समर्थन प्राप्त होगा। इसलिए, अध्यक्ष पद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद का विशेष सत्र 24 जून को शुरू होगा। हालांकि यह सत्र मुख्य रूप से लोकसभा में सभी निर्वाचित संसद सदस्यों की शपथ की पुष्टि के लिए है। तीसरे दिन, 26 जून को स्पीकर के लिए चुनाव होगा। फिलहाल ओम बिड़ला पिछले पांच साल से लोकसभा अध्यक्ष के पद पर हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला आज

बारबाडोस। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 का तीसरा मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों टीमें 20 जून यानी गुरुवार को भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से केनिंग्सटन ओवल, बारबाडोस में भिड़ेंगी।

केनिंग्सटन ओवल, बारबाडोस में अब तक कुल 47 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं जिसमें से 30 रन डिफेंड करने वाली टीम ने जीते हैं। ऐसे में साफ है कि रिकॉर्ड को देखते हुए बारबाडोस में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने चाहेगी। यहां पहली इनिंग का औसत स्कोर 138 रन रहा है।

हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यहां कि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर नजर आई है। ये भी जान लीजिए इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 244 रन बना है। बारबाडोस के मैदान पर आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ग्रुप राउंड के दौरान हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 201 रन बनाए थे।

दोनों टीमों का फुल स्क्वॉड

भारत- रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

अफगानिस्तान- रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जद्रन, नजीबुल्लाह जद्रन, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, नवीन अल हक, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, गुलबदीन नैब, करीम जनत, मोहम्मद इशाक, नांगयालिया खरोटे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 36.45 अंक चढ़ा तो निफ्टी 41.90 अंक टूटा

नईदिल्ली। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार शुरूआती बढ़त गवाने के बाद बुधवार को लगभग सपाट बंद हुआ। बाजार को कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिला और मुनाफावसूली के चलते बाजार गिरकर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज तेजी के साथ 77,543.22 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 77,851.63 अंक के स्तर तक चला गया था। अंत में सेंसेक्स 0.05 प्रतिशत या 36.45 अंक चढ़कर 77,337.59 अंक के ऑल टाइम हाई लेवल पर बंद हुआ। इसके उलट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.18 प्रतिशत या 41.90 अंक की गिरावट के साथ 23,516.00 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में एचडीएफसी बैंक का शेयर सबसे ज्यादा 3.06 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ। साथ ही एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस प्रमुख रूप से लाभ में रहे।

अदाणी ग्रुप एनर्जी ट्रांजिशन में निवेश करेगा

नईदिल्ली। अदाणी ग्रुप ऊर्जा बदलाव परियोजनाओं और विनिर्माण क्षमता में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को यह जानकारी दी। समूह का मकसद हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी सभी प्रमुख कलपुर्जों का विनिर्माण करना है। सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन करने के लिए सौर पार्क और पवन फार्म बनाने के अलावा समूह हरित हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा टर्बाइन और सौर पैनल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित कर रहा है। हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से पानी से हाइड्रोजन को विभाजित करके बनाया जाता है। इसे उद्योग के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र को कॉर्बन-मुक्त करने के लिए एक संभावित उपाय के रूप में देखा जा रहा है।

एयर इंडिया जुलाई से चुनिंदा घरेलू मार्गों पर प्रीमियम इकनॉमी श्रेणी शुरू करेगी

नईदिल्ली। एयर इंडिया अगले महीने से चुनिंदा घरेलू मार्गों पर प्रीमियम इकनॉमी श्रेणी शुरू करने जा रही है। यह श्रेणी उपलब्ध कराने वाली एयर इंडिया दूसरी भारतीय एयरलाइन कंपनी होगी। अभी तक सिर्फ विस्तारा ही घरेलू मार्गों पर प्रीमियम इकनॉमी यात्रा श्रेणी उपलब्ध कराती है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने बुधवार को कहा कि उसने दो नए ए320 नियो विमानों को तीन श्रेणियों में बांटा है। इनमें बिजनेस श्रेणी में आठ और प्रीमियम इकनॉमी में पैर रखने के लिए अतिरिक्त जगह के साथ 24 सीटें हैं। इसमें 132 इकनॉमी श्रेणी की सीटें भी होंगी। यह पहली बार है जब एयरलाइन ने अपने छोटे आकार के विमान में प्रीमियम इकनॉमी केबिन पेश किया है।

ठाणे के एक व्यक्ति ने शेयर कारोबार में गवाएं 94 लाख

मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के रहने वाले 48 वर्षीय एक व्यक्तिने शेयर कारोबार घोटाले का शिकार होकर 94 लाख रुपये गंवा दिये। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कल्याण क्षेत्र के इस व्यक्ति के साथ नौ अप्रैल से 21 मई के बीच धोखाधड़ी की गई। पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में व्यक्ति ने कहा कि वह द वैल्यू टीम ए 13 नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के संपर्क में आया जिसके कई सदस्य खुद को विशेषज्ञ बता रहे थे और शेयर बाजार के जरिए पैसा कमाने का गुप्त तरीका बता रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन विशेषज्ञों ने शिकायतकर्ता को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक और एप्लिकेशन का उपयोग करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया। पीड़ित व्यक्ति ने 93.6 लाख रुपये निवेश किए, लेकिन उसे कोई पैसा वापस नहीं मिला। अपने साथ हुए धोखे का एहसास होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

व्यापक विकास हो सरकार की प्राथमिकता

जीएन बाजपेयी

मोदी सरकार ने भारत को एक विकसित समाज बनाने और सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से लड़ने के महत्वपूर्ण संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों का संदेश तभी सही साबित होगा, जब भारत का विकास एकदम नीचे, सबसे कमजोर और गरीब तक पहुंचेगा। यह तभी संभव हो पायेगा, जब अगले दो दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत सालाना वृद्धि दर सात फीसदी से अधिक रहे। ऐसा कर पाना एक कठिन कार्य है। पारंपरिक साहित्य में जीडीपी वृद्धि मुख्य रूप से उत्पादन के तीन कारकों- भूमि, श्रम एवं पूंजी- की उपलब्धता एवं उत्पादकता से प्रभावित होती है। वर्तमान भू-राजनीतिक और वैश्विक परिदृश्य में हमें इन कारकों को सोच-समझकर और मेहनत से उपयोग में लाना होगा। इसके लिए इन क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

पूंजी क्षमता में तो भारत की सकारात्मक तुलना अधिकतर देशों से हो सकती है, पर श्रम उत्पादकता में हम बहुत पीछे हैं। वर्ष 2022 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2017 की क्रय शक्ति समता के आधार पर श्रम क्षमता के मामले में भारत को 126 स्थान पर रखा था। भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निजी कंपनियों तथा सरकारी-निजी भागीदारी के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी के लिए समुदाय के 80 प्रतिशत लोगों की सहमति जरूरी है। समुचित मुआवजे के अधिकार के साथ-साथ जमीन की खरीद बहुत कठिन और खर्चीली हो गयी है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग के विकास के लिए जमीन की उपलब्धता एक गंभीर बाधा बन गयी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अक्सर नकारात्मक होती है। हमें

अधिग्रहण के अधिक मानवीय तरीकों को अपनाना चाहिए, जिसमें लोगों के हित सुरक्षित रहें।

जीडीपी वृद्धि मुख्य रूप से उत्पादन के तीन कारकों- भूमि, श्रम एवं पूंजी- की उपलब्धता एवं उत्पादकता से प्रभावित होती है। वर्तमान भू-राजनीतिक और वैश्विक परिदृश्य में हमें इन कारकों को सोच-समझकर और मेहनत से उपयोग में लाना होगा। इसके लिए इन क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। पूंजी क्षमता में तो भारत की सकारात्मक तुलना अधिकतर देशों से हो सकती है, पर श्रम उत्पादकता में हम बहुत पीछे हैं।

वृद्धि दर बढ़ाने में कमतर कृषि क्षमता भी एक अवरोध है। यदि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों की तरह कृषि क्षेत्र ने भी योगदान दिया होता, तो वित्त वर्ष 2023-24 की वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक होती। ग्रामीण आबादी कृषि आय पर निर्भर है, जिसके कारण अधिक वृद्धि दर के आर्थिक लाभों से वह वंचित रह जाती है। भूमि, श्रम एवं खेती भावनात्मक मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दों पर भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सहमति बनाना एक लंबा संघर्ष है, जिसके लिए गंभीर धैर्य तथा विभिन्न हितों एवं विचारों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का राष्ट्रीय संकल्प आर्थिक मुक्ति के एक 'महायज्ञ' जैसा होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश तथा मतदाताओं की भलाई से सभी राजनीतिक रंगों के नेताओं को प्रेरित होना चाहिए तथा संकीर्ण हितों को छोड़कर सहमति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। कारोबारी सहूलियत के मामले में असली कांटा संविदा को लागू कराना है। इसमें औसतन 1,445 दिन लगता है और दावे के मूल्य में 31.3 प्रतिशत अधिक की वृद्धि हो जाती है। लोग न्यायिक अक्षमता से थक जाते हैं। न्यायपालिका में बड़े सुधारों की दरकार है। देरी से तंत्र के प्रति भरोसा भी घटता है। यहां भी संबंधित पक्षों में सहमति बनानी होगी।

थॉमस पिकेटी और अन्य अर्थशास्त्रियों की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वतंत्रता से अस्सी के दशक के शुरू तक विषमता में कमी आयी थी, परंतु 2000 से इसमें तेज बढ़ोतरी हुई है। इससे इंगित होता है कि उच्च जीडीपी से गरीबों का भला नहीं हुआ है।

सामूहिक जिम्मेदारी से दूर होगी सिकल सेल एनीमिया की बीमारी : साय

अखिल भारतीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है प्रस्तावः मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश 2047 तक विकसित भारत का रूप ले लेगा और इसी दौरान भारत से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अटल बिहारी वाजपेयी आडिटोरियम, मेडिकल कालेज, रायपुर में विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर अपना संबोधन दे रहे थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्व सिकल सेल दिवस पर सिकल सेल की स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होकर सिकल सेल जागरूकता रथ को रवाना किया और सिकल सेल से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिकल सेल पीड़ितों को जेनेटिक कार्ड का वितरण किया और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जागरूकता फैलाने के लिए सिकल सेल की जानकारी देने वाली हल्बी और गोंडी भाषा की पुस्तिका का विमोचन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सिकल सेल की जाँच और परीक्षण आवश्यक रूप से कराना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए सभी को जागरूक होना आवश्यक है। विवाह के पूर्व सभी महिला और पुरुष को सिकलसेल की जाँच करानी चाहिए और दोनों के पीड़ित होने पर शादी नहीं करनी चाहिए ताकि आनुवंशिक रूप से यह बीमारी अगली पीढ़ी मे स्थानांतरित न होने पाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग सिकलसेल एनीमिया से ज्यादातर पीड़ित हैं। इन पीड़ित मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग और आदिम जाति विकास विभाग के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिकलसेल के लिए राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च सेंटर प्रारंभ करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है ताकि प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया बीमारी से और बेहतर तरीके से बचाव किया जा सके।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों के लक्षित 1 करोड़ 77 लाख 69 हजार 535 सिकल सेल स्क्रीनिंग के विरूद्ध कुल 1 करोड़ 11 लाख 06 हजार 561 स्क्रीनिंग कर लिया गया है द्य इस परीक्षण में 1 करोड़ 06 लाख 24 हजार 245 स्क्रीनिंग निगेटिव पाए गए है। स्क्रीनिंग में 2 लाख 90 हजार 663 वाहक पाये गये हैं तथा 22 हजार 672 को बीमारी प्राप्त हुई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार सिकल सेल एनीमिया को छत्तीसगढ़ से पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

बाबू भैया की कलम से

हमने नहीं तूने किया से बलौदाबाजार हिंसा का नहीं होगा समाधान

बलौदाबाजार जैसी हिंसक घटना शायद ही भारत वर्ष भर में कहीं घटी हो। बेहद शर्मनाक घटना। जितनी निंदा की जाए कम है। निंदा लेकिन किसकी की जाए। उन लोगों की जो वहां इकट्ठा हुए थे। अपनी बात कहना चाहते थे। या उनकी जिन्होंने इन्हें इकठा करने बाकायदा पोस्टर सोशल मीडिया में डाल कर आंदोलन का आव्हान किया। या उनका जो दलगत वोट पॉलिटिक्स की वजह से भीड़ को नेतृत्व देने की होड़ कर रहे थे। सब जानते समझते हैं कि जिस सतनामी समाज का आंदोलन था ,उसके बीच नेता बनने का लोभ ना भाजपा और ना कांग्रेस और ना ही अन्य दल के नेता संवरण कर पाते हैं। सभी दल के नेतागण अपने दल की राजनीति चमकाने उस भीड़ में किसी ना किसी रूप में शामिल थे , यह कोई इनकार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में सब साफ दिखाई दे रहा है। दलों के नेता खुद इससे इनकार नहीं कर पा रहे हैं।लेकिन एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप धडल्ले से कर रहे हैं। सरकार से जुड़े लोगों पर उंगली उठाई जाती है तो कहा जाता है,सरकार हमारी है। हम खुद की सरकार को बदनाम करने का काम क्यों और किसलिए करेंगें। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत कहते हैं कि सरकार भाजपाइयों को बचाने का प्रयास कर रही है। पूर्व मुख्य मंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं व कांग्रेसियों को बेवजह टॉरगेट किया जा रहा है। घर घुस कर पुलिस द्वारा मारपीट की जा रहा है। बघेल ने सरकार से मांग की है कि अब तक कितने और कौन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ,उसकी सूची पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक की जाए। दोनों नेताओं का कहना है कि घटना साय सरकार की नाकामी, प्रशासन की पूरी लापरवाही,और लचर कानून व्यवस्था का परिणाम है। कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को अपनी कमी व लापरवाही को स्वीकार करना चाहिए और मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यह भी कहा गया कि जांच का दायरा व बिंदु भी ऐसे तय किये गए हैं ,जिसमें सरकारी तंत्र को जांच के घेरे से बचाने का प्रयास साफ झलकता है। मनखे मनखे एक समान का भाव रखने वाले सन्त घासीदास बाबा के अनुयायी सतनामी समाज के पवित्र गुफा में जैत खम्भ को तोड़ा गया। इतनी गंभीर घटना को सरकारी तंत्र ने व उसके खुफिया विभाग ने सामान्य रूप से देखा, ऐसा ही पूरी घटना को एकनजर में देखें तो साफ लगता है। सरकार-प्रशासन-खुफिया तंत्र कैसे नहीं समझ पाए की घटना यह रूप भी ले सकती है। जबकि बाकायदा पम्पलेट के माध्यम से एक संस्था ने खुले आम सतनामी समाज के लोगों को आह्वान किया कि विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनें। अब सबसे बड़ा संदेह तो उन्हीं पर जाना चाहिए , जिन्होंने यह आह्वान करके भीड़ जुटाई। भीड़ वह भी सतनामी समाज की, जो वोट बैंक का बहुत बडा हिस्सा प्रदेश में हो। यही समाज है जो एकजुटता के साथ किसी भी दल का साथ दे दे तो पासा पलट सकता है। ऐसे समाज का जमावड़ा एक जगह पर हो और वहां बोलने का मौका हो तो कौन से दल का नेता होगा जो इस मौके को गवाएंगा। भाजपा हो या कांग्रेस या कोई और दल का नेता वो बिन बुलाए ही वहां पहुंच जाएगा। अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ समाज को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव शाम -दाम-दंड-भेद की नीति के आधार पर अपनी बात वहां मजबूती से रखेगा ही।

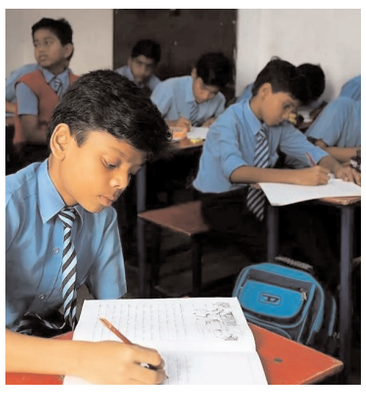

कहा यह भी जा रहा है कि किन्ही तत्वों ने असामाजिक तत्वों को षड्यंत्र की तहत भीड़ का हिस्सा बनाने भेज दिया गया और यह हिंसा हो गई। आश्चर्यजनक यह है कि हजारों की भीड़ में चंद असामाजिक तत्व घुस गए और उन्होंने भीड़ को उत्तेजित करने में सफलता पा ली तो फिर दलों के नेता किस काम के रहे। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जो तवे पे रोटी सेंकना तो अच्छे से जानते हैं,लेकिन रोटी को जलने से नहीं बचा पाते। वे किसी भी दल के हों लेकिन अपनी नेतृत्व क्षमता को अपने भीतर झांक कर आंकना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि उनमें बचाने व स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है तो किस बात के नेता। किस काम का उनका नेतृत्व। ऐसे सब लोगों को जो वहां मौजूद रहे उनको सारा सच मालूम है फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप क्यों। सच सबको स्वीकार करना चाहिए,गलती किसी की भी हो स्वयं की भी हो तो बाहर आनी चाहिए। नेता व नेतृत्वकर्ता तो उसी को कहते हैं।

शासन को विचारना होगा हमारा यह कैसा प्रशासन है जो जनता की तासीर को इतना भी नहीं समझ पाया कि ,वो क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है। प्रशासन सरकार तक स्थिति की वास्तविकता व जैत खम्भ की घटना को क्यों सही ढंग से नहीं पहुंचा पाया। लम्बे अंतराल तक गरमा गरमी चलती रही। अनेक बैठकें हुई। मांगे सामने आई। उस पर फैसला क्यों नहीं हो पाया। प्रशासन समाधान तक क्यों नहीं पहुंच पाया,निराकरण क्यों नहीं हो पाया। जिसके कारण सरकार को आज अपने बचाव में आने की जरूरत पड़ी। मंत्रीगणों को आरोप प्रत्त्यारोप पर उतरना पड़ा। खयाल रहे आरोप प्रत्त्यारोप का होना मूल घटना के तथ्यों से भटकाव का कारण भी बनता है। हमने वीभत्स झीरम हत्याकांड से सबक लेना चाहिए। जिसमें घटना के तत्काल बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगा दी गई थी। किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री रमनसिंह ने हत्या करवाई है। किसी ने उंगली अजीत जोगी पर उठाई। किसी ने शंका कवासी लखमा पर की। किसी ने कहा ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं हो सकता। किसी ने कहा सबूत मेरी जेब में है। किसी ने कहा जांच में सच सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर मामला आज तक उलझन में फंसा है। वैसी ही स्थिति इस मामले की ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। भले ही कोई हताहत नहीं हुआ हो लेकिन घटना उससे कम भी नहीं है। सैकंडों वाहन फूंक दी गई। कलेक्टर व एसपी कार्यालय को सरेआम जला दिया गया। करोड़ों की हानि हुई। भरपाई किससे होगी। भले ही गृह मन्त्री ने कह दिया हो कि भरपाई आरोपियों से की जाएगी। ऐसे बयान आते तो देखें हैं , लेकिन छत्तीसगढ़ में कभी ऐसी वसूली देखी तो नहीं है। आगे देखा जाएगा गृह मंत्री सच बोलते हैं या सिर्फ कोरी बयानबाजी है। भाजपा सरकार ने कलेक्टर व एसपी को ना सिर्फ वहां से हटाकर बल्कि आईएएस व आईपीएस को सस्पेंड भी करके एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से यह इशारा किया है की गलती किसी की नहीं है गलती इन दोनों अफसरों की है। क्योंकि आईएएस व आईपीएस अफसर की किसी बेहद गंम्भीर व प्रमाणित तथ्यो के प्रकट हो जाने पर ही स्पेंड करने की कार्यवाही की जाती है। प्रचलन तो यही है। कुल मिलाकर कोशिश यह होनी चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी घटना की पुनरावृति न हो।

कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग पर भड़के भाजपा अध्यक्ष, बोले-

अब किस मुंह से कर रही मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बलौदाबाजार आगजनी मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली कांग्रेस पर करारा कटाक्ष किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अपने शासनकाल में तमाम संघीय ढांचे को तहस-नहस करने पर आमादा भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई को प्रतिबंधित किया था, तो अब किस मुंह से कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है? उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस सरकार के शासनकाल में रक्षाबंधन के दिन बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार की दरिंदगी का काला अध्याय लिखा गया हो, शिक्षक दिवस के दिन एक आदिवासी शिक्षिका को सामूहिक दुष्कर्म की यंत्रणा से गुजरना पड़ा हो, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की जुमलेबाजी करने वाली प्रियंका वाड्रा की प्रदेश की राजधानी में मौजूदगी के बावजूद राजधानी के जयस्तभ चौक के पास पुलिस दफ्तर की नाक के नीचे एक युवती की अस्मिता को दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार करके लहूलुहान किया हो, राजधानी में गंडासा के जोर पर एक युवती को आतंकित कर घुमाया गया हो, और जिससे भूपेश सरकार का महिला और आदिवासी विरोधी चरित्र लगातार बेनकाब होता रहा हो, उस कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार को तो शर्म से गड़ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसियों के मगर शर्म फिर भी नहीं आ रही है और अब जातीय विद्वेष फैलाने के षड्यंत्र में अपनी भूमिका पर उठती जाँच की आँच से बेचैन कांग्रेसी कानून-व्यवस्था के नाम पर मगरमच्छ के आँसू बहाकर प्रदेश को भरमाने में लगे हैं।

प्रदेश के सभी स्कूलों में बनाया जाएगा स्मार्ट क्लासरूमः अग्रवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नये शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती, वेतन विसंगति, पदोन्नति, नई शालाओं के निर्माण समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर जानकारी ली। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं राज्य में शिक्षकों के 33 हजार रिक्त पदों पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से स्वीकृति के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इसके साथ ही राज्य में वेतन विसंगति और संयुक्त संचालक, उप संचालक, प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधानपाठक (माध्यमिक शाला) की पदोन्नति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया। मंत्री ने इन सारी विसंगतियां को जल्द से जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

छग में आरटीआई के तहत दाखिला लेने वाले प्राइवेट स्कूलों में मेंटरों की होगी नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राइट टू एजुकेशन के तहत प्रायवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए साय सरकार ने बड़ा फैसला किया है. छत्तीसगढ़ सरकार अब बच्चों गोद लेने जा रही ताकि छत्तीसगढ़ में ड्रॉप आउट पर अंकुश लग सके. बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए जिलेवार अफसरों को मेंटर बनाया जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए है.

स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा कि प्रायवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन पर कड़ी निगरानी रखें. इसके लिए वे खुद प्रायवेट स्कूल प्रबंधन को बुलाकर मीटिंग करे और आवश्यक निर्देश दें. अगर प्रायवेट स्कूलों में महंगी फीस, महंगी पुस्तकों की वजह से ड्रॉप आउट हो रहा तो उन स्कूलों पर कार्रवाई करें. स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके क्रियान्वयन के लिए जिलावार कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका अधिकारी की नौ सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.

मेंटर के दायित्व- मेंटर, प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लिए गरीब बच्चों के लिए सलाहकार और संरक्षक होंगे. वे स्कूल के साथ समन्वय कर समस्याओं का समाधान करेंगे, बच्चों के साथ सतत संपर्क बनाए रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कोई मानसिक परेशानी न हो, साथ ही, वे ड्रॉप आउट बच्चों की निगरानी करेंगे और स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाएंगे.

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

छगको मणिपुर जैसा बनाना चाहती है भाजपा सरकार

कोरिया/रायपुर। छत्तीसगढ़ से इकलौती कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान कोरबा लोकसभा से कांग्रेस सांसद ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को मणिपुर जैसा बनाना चाह रही है भाजपा सरकार। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही हिंसा और आगजनी, लड़ाई झगड़े जैसे काम शुरू हो गए हैं। सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि प्रदेश में कलेक्टर एसपी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा है कि देश मे जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां-वहां धर्म की आग लगी हुई है। भाजपा ने धर्म की आग लगाई है, उसे शांत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि आज से 20 साल पहले ऐसे हालात नहीं थे, आज धर्म जाति मजहब के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हुए बलौदाबाजार हिंसा पर भी सांसद ज्योत्सना महंत बोली हैं। उन्होंने कहा है कि जिसका नाम ही सतनाम हो, जो सत्य के ऊपर प्रेम के ऊपर बना हो। जैतखाम मामले को लेकर पहले कार्यवाही करना चाहिए तारीख का इंतजार क्यों किया गया। ज्योत्सना महंत का कहना है कि मेरे चुनाव में भी बाहरी लोगों ने कोरबा लोकसभा में डेरा डाला था.

अब मंत्रियों से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब मंत्रियों से मिलने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बिना अपॉइंटमेंट के मंत्रियों से मुलाकात करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारी कर्मचारी अधिकतर पर्सनल समस्या लेकर मंत्री के पास पहुंच जाते हैं। इस लिए अब यह नियम बनाया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है। अब किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मंत्री से मुलाकात करने पर अपॉइंटमेंट की जरुरत होगी। बिना अनुमति के मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अधिकारी-कर्मचार उचित माध्यम से विभागीय चैनल के जरिए अनुमति ले सकते हैं। अनुमति मिलने के बाद ही विभागीय मंत्री या फिर सीनियर अधिकारी से मिल सकते हैं। इसके लिए लिखित में आवेदन देना पड़ेगा। साथ ही दिए गए समय के उसके अनुसार ही मिलना पड़ेगा। अधिकारी-कर्मचारियों के बिना परमिशन लिए मिलने पहुंचने संबंधित कर्मचारी के काम पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही अनुशासन भी प्रभावित होता है। ऐसे में अब फिर विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता है। बिना अपॉइंटमेंट के मिलने पर कार्रवाई होगी।

भारतीय परिवार व्यवस्था की शक्ति पर रविवार को व्याख्यानमाला

रायपुर। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के पंचम सरसंघचालक सुदर्शन की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित व्याख्यानमाला की दशम कड़ी में - भारतीय परिवार व्यवस्था की शक्ति - पर रविवार 23 जून को शाम 5 बजे एक व्याख्यानमाला का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम (साइंस कालेज परिसर) में श्री सुदर्शन प्रेरणा मंच की ओर से किया गया है। व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता रामदत्त चक्रधर, सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री व अध्यक्षता डा. पूणेन्दू सक्सेना, मध्यक्षेत्र संघचालक, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ वीवाय हास्पिटल करेंगे।

डा. बेहार छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की सचिव नियुक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने डॉ अभिलाषा बेहार को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का सचिव नियुक्त किया है। शासन ने डा. बेहार को अगले एक साल की अवधि के लिए इस पद पर प्रतिनियुक्ति दी है। वर्तमान में डॉ अभिलाषा क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर में बतौर सहायक संचालक पदस्थ है।

लता व पुरदंर को मिल सकता है ओडीसा जीत का गिफ्ट

रायपुर। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधायक लता उसेंडी व रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा ने ओडीसा विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर मेहनत की थी,राज्य के अलग-अलग विधानसभा सीटों पर उन्होने रणनीतिक तरीके से प्रत्याशियों व स्थानीय नेताओं को लेकर काम किया और इसमें वे सफल भी रहे। पहली बार ओडीसा में भाजपा की सरकार बनी है। वैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर मंत्रियों,विधायकों व संगठन के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा था,लेकिन उसेंडी व मिश्रा को विशेष रूप से पार्टी से शाबासी मिल चुकी है और इस शाबासी के एवज में वे जल्द ही राजनीतिक गिफ्ट से नवाजे जाने वाले हैं। वैसे बृजमोहन अग्रवाल का रिक्त हो रहे मंत्री पद के अलावा एक पद पहले से खाली है मतलब दो विधायकों के लिए गुंजाइश यहां बन रही है। संभव है दोनों को समाहित कर लिया जाए। वैसे जिस अंदाज में टिकट लेकर आए और दमदारी के साथ चुनाव जीते पुरंदर मिश्रा का ग्राफ पार्टी में मजबूत बना हुआ है। ओडीसा जीत के बाद यह और पुख्ता हो गया है। अभी निगम मंडल आयोग के पद भी बचे हुए हैं। कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी भी दी जाती है।

काम में लापरवाही पर 5 अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में निर्माण कार्यों एवं दायित्व निर्वहन में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों के लिए नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पांच अधिकारियों के निलंबन का आदेश मंत्रालय से जारी किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का भुगतान करने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुमित मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

अनुशासन, साहस और निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए प्रेरित करता है एनसीसीः मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि एनसीसी ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन सिखाता है, चरित्र निर्माण करता है, साहसी बनता है और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। एनसीसी हमारे युवाओं को सेना और अन्य सुरक्षा बलों में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। मुख्यमंत्री आज अपने निवास परिसर में आयोजित एनसीसी कैडेट और प्रशिक्षकों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनसीसी के अधिकारियों और कैडेट्स को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही गौरव का क्षण है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राज्य के एनसीसी कैडेट्स को परेड करते हुए देखना बड़ा ही सुखद होता है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्य के किसी कैडेट का चयनित होना न सिर्फ उस कैडेट के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एनसीसी का ध्येय वाक्य ही है- 'एकता और अनुशासन' और इसी पर चलते हुए एनसीसी ने राष्ट्र प्रेम को सींचा है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। श्री साय ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि एनसीसी में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हमारी बच्चियों ने राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक एनसीसी का नेतृत्व कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज भारत की उपलब्धियों का गौरवगान पूरी दुनिया कर रही है। इन उपलब्धियों में निश्चित रूप से युवाओं की बड़ी भागीदारी है।हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। हमारे ऊर्जावान युवाओं के योगदान से हम सब अवश्य ही इस लक्ष्य को हासिल करेंगे और अपने देश को दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भविष्य में जो भी काम करें, हमेशा याद रखें कि आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर एनसीसीसी द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षुओं और कैडेट को सम्मानित किया। सम्मान समारोह के अंत में कैडेट्स द्वारा बैगा जनजाति पर आधारित नृत्य और कुचीपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई।

एनसीसी के अधिकारियों ने एनसीसी रायपुर ग्रुप के उपलब्धियां की जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह देश का सबसे बड़ा एनसीसी ग्रुप है जिसमें 16 यूनिट संचालित है। एनसीसी रायपुर ग्रुप में 342 शैक्षणिक संस्थान संबद्ध है, इसमें तकरीबन 23 हजार स्टूडेंट है, जिसमें 43त्न लड़कियां है। इस वर्ष 2024 के रिपब्लिक डे परेड के के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें कुल 25 महिला कैडेट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें चार कैडेट छत्तीसगढ़ की थी, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। साथ ही उन्होंने एनसीसी रायपुर ग्रुप द्वारा संचालित गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में शामिल कैडेट्स और प्रशिक्षक हुए सम्मानित

छत्तीसगढ़ के लोगों के स्किल अपग्रेडेशन के लिए कंपनियां करें काम : साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से यहां मंत्रालय में निवेशकों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेश करने में रूचि दिखाई। इन निवेशकों में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और आईटी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी टेलिपरफॉर्मेंस शामिल हैं। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जशपुर में ग्रीन फील्ड सोलर प्लांट की स्थापना तथा नवा रायपुर अटल नगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने में रूचि दिखाई है। कंपनी की योजना जशपुर में 400 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने की है। इसी तरह टेलिपरफॉर्मेंस कंपनी आईटी एवं आईटीज के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है, जिसने नवा रायपुर अटल नगर में 500 सीटर क्षमता का बीपीओ स्थापित करने में रूचि दिखाई है। मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि कंपनियों की जरूरत के मुताबिक छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी स्किल बढ़ाई जाए और उन्हें स्थापित की जाने वाली इकाईयों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाएं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.